सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन साइकिल चलाने जैसा है,
बैलेंस बनाये रखने के लिए आपको चलते रहना है।

वर्ष 01, अंक 204, नई दिल्ली

शुक्रवार, 06 अक्टूबर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

नितिन गडकरी ने की थी घोषणा: अब पश्चिम बंगाल और बिहार से होगा यूपी का सीधा जुड़ाव, होने जा रहा ये काम

परिवहन विशेष। एसडीसेठी।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से सीधे गंगा पर पुल का निर्माण कराकर ताड़ीघाट-बारा हाईवे को बारा के समीप जोड़ने की योजना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए जरूरी धनराशि भी जारी की है। फिलहाल अभी जमीन के अधिग्रहण की भी प्रक्रिया होनी है।

अब पश्चिम बंगाल और बिहार का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा जुड़ाव होगा। इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को पश्चिम बंगाल जाने वाले एनएच 2 से जोड़ने के लिए गाजीपुर जिले के शेरपुर एवं बारा के बीच गंगा नदी पर दो लेन का एक पक्का पुल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। एनएचएआई द्वारा तैयार डीपीआर को हरी झंडी मिल जाने के बाद महकमा इसमें जुट गया है। पुल के दोनों तरफ दो लेन की सड़क भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 13 किमी लंबी दो लेन की सड़क भी बनाई जाएगी।

केंद्र सरकार ने इसके लिए जरूरी धनराशि भी जारी की है। फिलहाल अभी जमीन के अधिग्रहण की

भी प्रक्रिया होनी है। पुल के निर्माण पूरा होने एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से एन एच 31 होते हुए पश्चिम बंगाल जान वाला एनएच टू एक शार्टकट बाइपास मार्ग भी होगा, जो काफी फायदेमंद होगा पश्चिम बंगाल से प्रदेश की राजधानी लखनऊ काफी कम समय में सफर आसान हो सकेगा।

बीते फरवरी माह में बलिया आए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों की मांग पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को सीधे एनएच 2 पश्चिम बंगाल जाने वाले राजमार्ग से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पक्का पुल बनाने का एलान किया था।

केंद्र सरकार से करीब 400 करोड़ रुपये की मंजूरी

बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के मुताबिक पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और पश्चिम बंगाल जाने वाले एनएच 2 को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से करीब 400 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। वही, माल्देपुर से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए 100 करोड रुपए की मंजूरी भारत सरकार ने दी है। सांसद ने बताया कि पुल बन जाने से बिहार को जोड़ने वाली ताड़ीघाट-बारा नेशनल हाईवे 124सी भी सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं पश्चिम बंगाल जाने वाली एनएच 2 से जुड़ जाएगा। इसके बाद पूरे यूपी से बिहार व पश्चिम बंगाल जुड़ जाएगा।

इसका सीधा फायदा जनपद ही नहीं विभिन्न प्रांतों को भी मिलेगा। इससे जहां मार्ग की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहीं लोगों को रोजगार और उद्योग-धंधे के लिए किसी अन्य प्रांतो में पलायन नहीं करना पड़ेगा। एनएचएआई आजमगढ़ के परियोजना निदेशक एसपी पाठक ने बताया कि बनाए जाने वाले पुल व सड़क के लिए डीपीआर को हरी झंडी मिल चुकी है।

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm.

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Font Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-
- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/Back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को बड़ी सफलता, सुरंग के लिए सिर्फ 10 महीने में चीर डाला पहाड़ का सीना

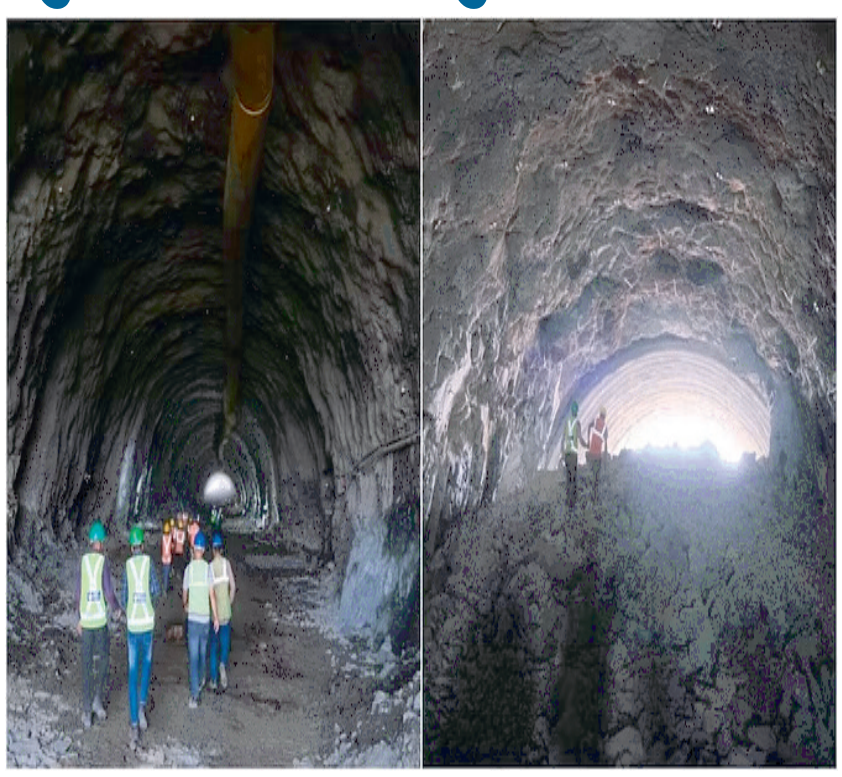

परिवहन विशेष न्यूज

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने में जुटी टीम ने पहाड़ सी चुनौती को बौना साबित कर पहली पहाड़ी सुरंग केवल 10 महीने में बनाने की उल्लेखनीय कामयाबी पाई है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक है। जिन रास्तों पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, उसमें कई जगह पहाड़ काटकर सुरंग बनाने की चुनौती भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में जुटी टीम ने हर चुनौती को बौना साबित करने का संकल्प लेकर काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार टीम ने पहली पहाड़ी सुरंग केवल 10 महीने में बना दिया है। बुलेट ट्रेन की परियोजना में वलसाड में बनी सुरंग उल्लेखनीय कामयाबी है।

केवल 10 महीने में बनी सुरंग

रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कुल सात पर्वतीय सुरंग बनाए जाने हैं। पहली सुरंग बनाने में 'सफलता' गुरुवार को मिली। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के अनुसार, गुजरात के वलसाड में केवल 10 महीने की अवधि में सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक रास्ता बनाने में कामयाबी मिली।

देश में पहली बार समुद्र के नीचे सुरंग, खुदाई का काम शुरू

एक अधिकारी के अनुसार, छह और पर्वतीय सुरंगों के लिए भी ठेके दिए जा चुके हैं। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को पड़ोसी ठाणे जिले में शिलफाटा से जोड़ने वाले रूट पर समुद्र के नीचे सुरंग बनाना है। इसके लिए भी खुदाई का काम शुरू हो चुका है।

ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाई गई सुरंग

एनएचएसआरसीएल ने बताया कि वलसाड में जिस सुरंग को तैयार करने में 'सफलता' हासिल हुई है, वह पड़ोसी राज्य वलसाड के उमरगांव तालुका में ज़ारोली से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) का उपयोग करके बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 'ब्रेकथ्रू' एक इंजीनियरिंग शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब एक सुरंग के दो सिरे बीच में मिलते हैं।

सुरंग घोड़े की नाल के आकार की, दो हाईस्पीड ट्रैक होंगे

इस रसंरचना में एक सुरंग, एक सुरंग पोर्टल और एक सुरंग प्रवेश द्वार हुड जैसी अन्य कनेक्टिंग संरचनाएं भी शामिल हैं। 350 मीटर लंबी सुरंग की गोलाई 12.6 मीटर और ऊंचाई 10.25 मीटर है। यह एकल ट्यूब सुरंग घोड़े की नाल के आकार की है। सुरंग में दो हाई-स्पीड ट्रेन ट्रैक होंगे।

सात पहाड़ी सुरंग बनानी है, जानिए पूरा प्रोसेस

रिपोर्ट के अनुसार मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में सात पहाड़ी सुरंगें होंगी। इनमें से सभी का निर्माण एनएटीएम का उपयोग करके किया जाएगा। पूरे प्रोसेस में सुरंग के सिरे पर ड्रिल छेद को चिह्नित करना, ड्रिलिंग छेद, विस्फोटकों को चार्ज करना, नियंत्रित ब्लास्टिंग, मलबा हटाना और प्राइमरी सपोर्ट इंस्टॉल करना शामिल है।

समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग का लोकेशन जानिए

हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर में मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ठाणे जिले के शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इस संरचना का 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे होगा। ये जगह देश की पहली ऐसी सुरंग के लिए मशहूर होगी जहां समुद्र के नीचे सुरंग बनी होगी।

पालघर में बनेगी सुरंग

अधिकारियों ने कहा कि जिन छह पर्वतीय सुरंगों के लिए ठेके दिए गए हैं, मुंबई से इनकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के कसाबेकामन, चंद्रपाड़ा, चंदसर, मीठागर, वसंतवाड़ी और अंबेसरी में सुरंग का निर्माण कराया जाना है।

बुलेट ट्रेन की कुल लागत, जापान से लोन

बता दें कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की कुल लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, भारत सरकार एनएचएसआरसीएल को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। परियोजना में शामिल दो राज्य- गुजरात और महाराष्ट्र 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। बाकी अमाउंट की भरपाई जापान से लिए गए लोन से होगी।

मेट्रो की सभी लाइनों पर व्हाट्सएप से खरीद सकेंगे टिकट, मोबाइल में सेव कर लें यह नंबर

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपने स्मार्टफोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में डीएमआरसी का व्हाट्सएप नंबर जोड़ना होगा। शुरुआती और गंतव्य स्टेशनों का नाम बताने पर क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे एएफसी गेट पर दिखाकर प्रवेश या गंतव्य स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों को अब टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सभी लाइनों पर व्हाट्सएप से टिकट खरीदने की सुविधा शुरू की है। इससे टिकट के लिए यात्रियों को लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर उपलब्ध थी। इसकी सफलता को देखते हुए डीएमआरसी ने अब गुरुग्राम रैपिड मेट्रो सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सभी लाइनों को कवर करने के लिए इस अत्याधुनिक सेवा का विस्तार किया है।

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपने स्मार्टफोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में डीएमआरसी का व्हाट्सएप नंबर 9650855800 जोड़ना होगा। इसमें शुरुआती और गंतव्य स्टेशनों का नाम बताने पर क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे एएफसी गेट पर दिखाकर प्रवेश या गंतव्य स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। इससे खासतौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो रोज मेट्रो से सफर करते हैं। इससे वह घर बैठे ही टिकट की बुकिंग कर सकते हैं।

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने कहा कि मेट्रो यात्रियों को एक साधारण चैट के माध्यम से टिकट खरीदने का विकल्प प्रदान करने से उनके यात्रा अनुभव में काफी वृद्धि होगी। व्हाट्सएप पसंदीदा है, अधिकांश लोगों के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और मेट्रो टिकट खरीदना अब किसी मित्र या परिवार के सदस्य को मैसेज करने जितना आसान होगा।

आसानी से खरीद सकेंगे क्यूआर टिकट

-स्मार्ट फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में डीएमआरसी का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9650855800 जोड़ना होगा।

-सभी स्टेशनों के ग्राहक सेवा या टिकट काउंटरों पर प्रदर्शित चैटबॉट क्यूआर कोड सीधे कर सकेंगे स्कैन।

-व्हाट्सएप खोलने के बाद Hi लिखकर डीएमआरसी के नंबर पर भेजना होगा।

-अपनी पसंदीदा भाषा चुनकर टिकट खरीद सकते हैं। अंतिम यात्रा टिकट या टिकट दोबारा प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

यह हैं खूबियां

-एकल यात्र या समूह टिकट के लिए अधिकतम 6 क्यूआर टिकट खरीद सकते हैं।

-मेट्रो सेवा के शुरू होने से पहले या रात के वक्त समाप्त होने के बाद टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे।

-क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किए ट्रांजेक्शन पर मामूली सुविधा शुल्क लिया जाएगा।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

प्रेग नेंसी में मोबाइल रेडिएशन से दूरी बनाना जरूरी वरना शिशु को हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम

अगर गर्भवती महिला के आसपास अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन है, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है. यही नहीं, बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है. जानें, प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल रेडिएशन से अजन्मे बच्चे के विकास में क्या समस्या आ सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है. हम सभी सुनते आए हैं कि अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है. खासतौर पर प्रेग्नेंट महिला और उसके पेट मे पल रहे बच्चे के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पेट में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी तक हो सकती है. केवल मां ही नहीं, अगर मां के आस पास लोग वायरलेस चीजों का अधिक इस्तेमाल कर रहे है तो इसका भी भ्रूण में पल रहे बच्चे पर खराब असर पड़ सकता है. मॉमजंक्शनमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में किए गए शोध में पाया गया है कि अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन में अगर गर्भवती मां रहती है तो जन्म के बाद बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. यही नहीं, इसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं.

वायरलेस डिवाइस कैसे करता है प्रभावित

दरअसल जब हम मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह के वाइफाई या वायरलेस डिवाइस के संपर्क में आते हैं तो इससे हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स निकलते रहते हैं. ये वेव्स हमारे शरीर के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं और हमारे शरीर में बन रहे जीवित सेल्स के मोलक्यूल्स को बदल सकते हैं. जिसका असर लॉग टर्म काफी खतरनाक हो सकता है. चूंकि भ्रूण हर वक्त ग्रोथ कर रहा है ऐसे में उसके डीएनए और लीविंग सेल्स आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं. जिसका दूरगामी असर भी काफी खतरनाक हो सकता है.

क्या कहता है शोध

अलग अलग शोधों में पाया गया कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन अगर मां और बच्चा 24 घंटे मोबाइल रेडिएशन के बीच हैं तो बच्चे की मेमोरी, ब्रेन ग्रोथ और बिहेवियर में खतरनाक रूप से समस्या आ सकती है. शोधों में यह भी पाया किया गया कि प्री और पोस्ट डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. यही नहीं, बच्चे की भाषा, संचार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

इस तरह करें बचाव

- घर में जहां तक हो सके वाई फाई या ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल कम करें.
- बेहतर होगा अगर आप मोबाइल की बजाय लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल करें.
- रेडियो, माइक्रोवेव, एक्सरे मशीन आदि से दूरी बनाएं.
- मोबाइल टावर आदि के आस पास घर ना लें.

गर्भावस्था में मोबाइल के नुकसान

-गर्भवती महिलाओं में रेडिएशन से मस्तिष्क की गतिविधि पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे थकान, चिंता और नींद में रुकावट पैदा होती है.
-गर्भावस्था के दौरान रेडियो वेव्स के लगातार संपर्क से आगे जाकर कैंसर का खतरा बन सकता है.
-मां गर्भावस्था के दौरान फोन का अधिक इस्तेमाल करे या काफी करीबी लोग घर पर इसका इस्तेमाल करें तो बच्चे के व्यवहार में 50 प्रतिशत बदलाव देखने को मिलता है.

-ऐसे बच्चे अधिक एग्रेसिव और हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं.

उम्र हो रही है 40 के पार? 20 की एनर्जी और नूर के लिए डाइट में शामिल करें 6 चीजें, हेल्थ भी रहेगी दुरुस्त

चालीस की उम्र में आते-आते हर महिला की लाइफ में कई बदलाव आते हैं, जिसके चलते सेहत सम्बन्धी कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं. वहीं एनर्जी लेवल भी कम होने लगता है, जिसके चलते चेहरे का नूर भी फीका पड़ने लगता है. आप 40 की उम्र में भी 20 वाला निखार और एनर्जी बनाए रखना चाहती हैं तो आपको कुछ चीजों (Anti Aging Food) को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. हेल्थलाइन डॉट कॉम के अनुसार, आपको बताते हैं महिलाओं की डाइट के लिए जरूरी चीजों के बारे में.

आज की महिला घर के साथ साथ बाहर जाकर काम करने में भी सक्षम है। किन्तु प्रत्येक दिन की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वह अपने शरीर, दिल और दिमाग का ध्यान रखना भूल जाती हैं। ऐसी बहुत सी समस्यायें होती हैं जिनपर महिलायें ध्यान नहीं देती और यही छोटी छोटी समस्याएं भविष्य में भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। महिलायें अपने परिवारजनों का ध्यान तो रखती हैं परन्तु स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं।

परिवार और प्रियजनों का ध्यान रखने के लिए महिलाओं को सर्वप्रथम स्वयं को स्वस्थ रखना होगा। यहाँ हमने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुडी कुछ महत्वपूर्ण और आसान हेल्थ टिप्स – Health Tips in Hindi for women Body के बारे में बताया है। इन टिप्स की सहायता से वे अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव ला सकेंगी साथ ही सही आहार, व्यायाम और तनाव-राहत योजना भी आसानी से कर पायेंगी।

प्रतिदिन व्यायाम/ एक्सरसाइज करें
अपना वजन कम करें (वजन नियंत्रित रखें)
समय समय पर डॉक्टर के पास जाएँ
तनाव कम करें

एक महिला ही नहीं अपितु किसी भी मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है कि उसका दिल, दिमाग और शरीर स्वस्थ रहे। यहाँ हमने एक महिला के लिए कुछ टिप्स बताये हैं कि कैसे वह अपने दिल दिमाग और शरीर को स्वस्थ रख सकती है। उसके बाद हम इस लेख में कुछ अन्य हेल्थ टिप्स के बारे में बताएंगे। आइये जानते हैं कैसे एक महिला अपने दिल दिमाग और शरीर को स्वस्थ रख सकती है –

अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाएं।
साबुत अनाज चुनें, सफेद की जगह ब्राउन राइस ट्राई करें। मैदा की जगह, गेहूं से बने पास्ता खाएं ।
चिकन, मछली, सेम, और फलियां जैसे लीन प्रोटीन को चुनें।
अत्यधिक प्रोसेस्ड फ़ूड, चीनी, नमक, और सैचुरेटेड फैट में कटौती करें।

प्रतिदिन व्यायाम/ एक्सरसाइज करें

आप जितने सक्रिय रहते हैं, उतना ही बेहतर होता है। नित्य व्यायाम हमारे दिल को हेल्दी बनता है, मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बढ़ाता है, और अभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करता है।

सप्ताह में 2 से 4 घंटे की मध्यम गतिविधि, जैसे तेज चलना या नृत्य अवश्य करें। इसके अलावा आप सप्ताह में 1 घंटा 15 मिनट दौड़ने या टेनिस खेलने जैसी क्रियाएं भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी शक्ति और ताकत बढ़ाने पर भी ध्यान दें।

यदि आप ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो पूरे दिन छोटी-छोटी गतिविधियाँ करने की कोशिश करें। जितना हो सके चलें, एक दिन में कम से कम 10,000 कदम चलने का लक्ष्य बनाएं।

अपना वजन कम करें (वजन नियंत्रित रखें)

यदि आप अपना वजन नियंत्रित रखते हैं, तो आपको हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसके लिए आप धीरे धीरे अपना वजन कम (सप्ताह में 1-2 पाउंड) करें- सक्रिय रहें और अच्छी डाइट लें।

वजन कम करने के लिए व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप बहुत अधिक वजन कम करना चाहते हैं, तो सप्ताह में 300 मिनट व्यायाम करने का प्रयास करें।

स्वस्थ आहार खाने से आप जल्दी ही अपना वजन कम कर सकते हैं। अपने डाइट से शुगर को कम करें, सोडा और चीनी युक्त कॉफी पेय से भी बचने की कोशिश करें।

समय समय पर डॉक्टर के पास जाएँ

समय समय पर अपने शरीर की नियमित जांच करवाते रहें। आपका डॉक्टर आपके मेडिकल हिस्ट्री की मदद से आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। आपका डॉक्टर आपके स्वास्थ्य की जाँच करने और इलाज के सही विकल्पों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षणों की सिफारिश कर सकता है।

अपने स्वास्थ्य से सम्बंधित मुद्दों पर अपने डॉक्टर से बात करते रहें। "यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछें"। यदि आप किसी दवा या प्रक्रिया के बारे में चिंतित हैं, तो उसके बारे में उससे बात करें।

तनाव कम करें

यदि आप तनाव या स्ट्रेस लेती हैं तो यह आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। आप इसे पूरी तरह से टाल नहीं सकती हैं, लेकिन आप इसके प्रभाव को कम करने के तरीकों को जानकर इसपर नियंत्रण कर सकती हैं।

यदि आप तनाव दूर करना चाहती हैं तो प्रयास करें:

गहरी साँस लेना
ध्यान
योग
और योगासन
मालिश
व्यायाम
पौष्टिक भोजन
किसी मित्र, परिवार के सदस्य या पेशेवर परामर्शदाता से बात करना
पूरे दिन में अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को समय अवश्य दें।

अखिल भारतीय मानव क कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक डॉ हृदयेश कुमार ने बताया कि

स्ट्रेस कम लें: जितना हो सके महिलाओं को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस या तनाव से बांझपन से लेकर डिप्रेशन, चिंता, और हृदय रोग होने के उच्च जोखिम जुड़े होते हैं।

ऐसे भोजन का सेवन कम करें जोजो फैट युक्त और कैलोरी युक्त हो। अपने भोजन में लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट, स्मार्ट कार्ब्स और फाइबर को शामिल करें।

अत्यधिक कैल्शियम न लें: बहुत अधिक अवशोषित कैल्शियम गुर्दे की पथरी के खतरे को बढ़ा सकता है और यहां तक कि हृदय रोग के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। यदि आप 50 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो प्रति दिन 1,000 मिलीग्राम से अधिक कैल्शियम न लें, जबकि 50 से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति दिन 1,200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए।

कार्डियो व अन्य एक्सरसाइज: महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह को रोकने में मदद करने के लिए सप्ताह में कम से कम तीन से पांच बार कार्डियो और वजन उठाने वाली एक्सरसाइज जैसे डंबल उठाना इत्यादि करनी चाहिए। व्यायाम भी अच्छी आत्म-छवि को बढ़ावा देता है, जो वास्तव में एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

जन्म नियंत्रण (बिरथ कण्ट्रोल) की सराहना करें: जन्म नियंत्रण को बुरा माना जाता है, लेकिन एक अध्ययन से पता चलता है कि यह न केवल आपके तैयार न होने पर आपको गर्भवती होने से रोक सकता है, बल्कि यह गर्भाशय और ओवेरियन कैंसर के जोखिम को भी कम कर सकता है और साथ ही साथ आपके पीरियड्स को नियंत्रित कर सकता है।

भरपूर नींद लें: आयु के साथ साथ नींद की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं, लेकिन अगर आपको बिस्तर से बाहर निकलने में परेशानी होती है, आसानी से थक जाते हैं, या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, तो अवश्य ही आप पर्याप्त रूप से नींद नहीं ले रहें हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि यह आपको हृदय रोग और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के जोखिम में डाल सकता है।

आजकल डॉक्टर स्तन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और पुरानी बीमारियों के पारिवारिक इतिहास वाले लोगों की स्क्रीनिंग भी करते हैं और फिर इसके निवारक उपायों पर विचार करके सही उपचार करते हैं। ऐसी किसी समस्या के लिए आज ही अपने डॉक्टर से बात करें।

शराब और धूम्रपान न करें: यदि आप स्वस्थ रहना चाहती हैं तो सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखने कि शराब और धूम्रपान न करें। इस प्रकार के व्यसन अनेक बीमारियों और कैंसर, हृदय रोग जैसी जानलेवा बीमारियों को आकर्षित करते हैं। कोशिश करें इनका सेवन न करें।

मौखिक स्वास्थ्य पर दें ध्यान: आमतौर पर देखा जाता है कि हम मोखिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान नहीं देते। शरीर के अन्य भागों के समान मौखिक स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रातः उठकर और सोने से पहले अपने दाँतों को अवश्य साफ़ करें और किसी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत डेंटिस्ट को दिखाएँ।

इन सभी आसान हेल्थ टिप्स को अपनाकर एक महिला अपने आपको स्वस्थ रख सकती है। ये सभी टिप्स और योजनाएं उसके दिमाग ही नहीं दिल और शरीर का भी ध्यान रखेंगी।

जो महिलाएं मां नहीं बन पातीं, उनमें हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा: नई रिसर्च

महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है.

महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है. (सांकेतिक तस्वीर) महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है.

ब्रिटेन में हुई रिसर्च से पता चला है कि जिन औरतों में बांझपन (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका 16 फीसदी तक ज्यादा होती है. महिला को गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ में परेशानी हो तो बाद के सालों में दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है.

प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी

प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी

लंदनः एक नए शोध से पता चला है कि महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने (infertility) की समस्या का संबंध दिल की बीमारी से भी होता है. ब्रिटेन में हुई रिसर्च के बाद दावा किया गया है कि जिन औरतों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका बाकी महिलाओं से 16 फीसदी तक ज्यादा होती है.

अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जर्नल में छपे इस शोध में कहा गया है कि महिलाओं के प्रजनन इतिहास से काफी हद तक पता चल जाता है कि उन्हें भविष्य में दिल की बीमारी होने का कितना खतरा है. महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है. इस शोध के दौरान दो तरह के हृदयाघात यानी हार्ट फेल होने की स्टडी की गई. पहला preserved ejection fraction के साथ हार्ट अटैक (HFpEF) जिसमें दिल की मांसपेशियां खून पंप करने के बाद पूरी तरह फैल नहीं पातीं. दूसरा हार्ट फेल्योर विद reduced ejection fraction (HFrEF). इसमें बाएं वेंट्रीकल यानी दिल के निचले भाग के कोष से हर धड़कन के बाद जितना खून शरीर में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता. महिलाओं में हार्ट फेल के ज्यादातर मामले HFpEF के ही होते हैं. शोध करने वाली टीम की लीडर और मैसाचूसेट्स जनरल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एमिली लाउ ने बताया कि रिसर्च के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि महिलाओं में थायरायड या जल्दी मेनॉपॉज़ जैसी समस्याओं का भी क्या प्रजनन क्षमता और दिल की बीमारी से कोई लेना-देना होता है या नहीं. लेकिन इस धारणा को लेकर किसी तरह के पुख़्ता सबूत अभी नहीं मिल पाए हैं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी तक ये तो पता था कि जिन महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की समस्या होती है, उनमें हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांस ज्यादा होते हैं. लेकिन बांझपन का दिल की बीमारी पर असर को लेकर कोई पुख्ता स्टडी नहीं हुई थी. आमतौर पर दिल की बीमारी को 50 साल के बाद की समस्या माना जाता है, जबकि बांझपन उम्र के 20वें, 30वें या 40वें पड़ाव पर आने वाली दिक्कत है. इसलिए इन दोनों के संबंध पर गौर नहीं किया जाता. अब महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की क्षमता का कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन भविष्य का ध्यान तो रखा ही जा सकता है ताकि उन्हें दिल की बीमारियों से बचाया जा सके.

संजय सिंह के घर पर हुआ तीन करोड़ का लेन-देन, रिमांड पर लेकर अब क्या करेगी ईडी

आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप AAP) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को दस अक्टूबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने गुरुवार को संजय सिंह को अदालत के समक्ष पेश करके दस दिन के रिमांड की मांग की।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप, AAP) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को दस अक्टूबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने गुरुवार को संजय सिंह को अदालत के समक्ष पेश करके दस दिन के रिमांड की मांग की।

ईडी ने संजय सिंह के आवास पर दो मौकों पर तीन करोड़ रुपये की राशि का आदान-प्रदान होने का तर्क भी दिया। वहीं, बचाव पक्ष ने ईडी की दलीलों को ठुकराते हुए रिमांड आवेदन का विरोध किया।

पेशी से पहले क्या बोले संजय सिंह?

दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को पांच दिन के लिए ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। अदालत में ईडी द्वारा पेशी पर लाने के दौरान संजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नाइंसाफी है और उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव हारेगी। बुधवार को ईडी ने करीब 11 घंटे तक चली छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।

डिजिटल साक्ष्यों से सामना कराने के लिए हिरासत आवश्यक: ईडी

ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजन नवीन मट्टा ने कहा कि दो किश्तों में कुल तीन करोड़ का लेनदेन हुआ है। ईडी ने कहा कि उक्त धनराशि संजय सिंह के आवास पर दी गईं। दिनेश अरोड़ा ने इसे संजय सिंह से क्रॉस-चेक किया था और उन्होंने इसकी पुष्टि की थी।

जांच में पता चला है कि कुछ तीन करोड़ में से दो करोड़ रुपये नकद दिए गए थे। ईडी ने कहा कि आबकारी घोटाला मामले में अब तक कुल 239 स्थानों की तलाशी ली गई है। मोबाइल से लेकर डिजिटल सुबूतों से सामना कराने के लिए ईडी द्वारा रिमांड की मांग करने पर अदालत ने कहा कि यह तो बगैर कस्टडी के भी किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि आप मोबाइल फोन का सीडीआर ले सकते हैं और जब फोन आपके पास है तो फिर सामना कराने जैसा क्या है। ईडी ने कहा कि कई अहम व्यक्तियों का परीक्षण किया जाना है।

अरोड़ा ने अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए संजय सिंह को फंसाया- बचाव पक्ष

10 दिन के रिमांड के ईडी के आवेदन का विरोध करते हुए संजय सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए दस दिन के रिमांड की मांग करना बेतुका प्रस्ताव है, जोकि इसमें शामिल ही नहीं था। मामला शराब नीति से संजय सिंह का कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए संजय सिंह को फंसाया है। उन्होंने तर्क दिया कि दिनेश अरोड़ा के बदले रुख को अदालत को देखना चाहिए। दिनेश अरोड़ा मार्च और अप्रैल में बयान देते हैं, लेकिन संजय सिंह का नाम नहीं आता है। अचानक से वह सरकारी गवाह बनकर नाम लेते हैं और उन्हें जमानत मिल जाती है।

उन्होंने ईडी पर सिंह को गिरफ्तार कर अपमानित करने का आरोप लगाया। मोहित माथुर ने अरोड़ा को मामले में सिंह को फंसाने के लिए मजबूर करने का दावा किया। हालांकि, ईडी के अधिवक्ता शोएब हुसैन ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रलोभन के आधार पर दिनेश अरोड़ा द्वारा बयान देने का तर्क पूरी तरह से निराधार है।

अमित और दिनेश अरोड़ा को पहले याद नहीं आया मेरा नाम- संजय सिंह

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष संजय सिंह ने कहा कि मैं कोई अनजान व्यक्ति नहीं हूं कि अमित अरोड़ा व दिनेश अरोड़ा को मेरा नाम याद नहीं आया। इससे पहले दिन गए अपने कई बयानों में उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सारा बयान मेरे खिलाफ दिया।

दिनेश अरोड़ा और सिसोदिया के बीच की कड़ी थे संजय सिंह, ED ने सांसद पर लगाए हैं ये आरोप; अब सामने आ रहे छिपे

आबकारी घोटाले (Delhi Excise Policy) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में ईडी (ED) की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है उसके साथ ही कई राज से पर्दा उठने लगा है। जांच में सामने आया है कि दक्षिण भारत की लॉबी के अलावा शराब और रेस्तरां कारोबारी दिनेश अरोड़ा और AAP नेता और दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच की कड़ी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ही थे।

नई दिल्ली। आबकारी घोटाले (Delhi Excise Policy) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में ईडी (ED) की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, उसके साथ ही कई राज से पर्दा उठने लगा है। जांच में सामने आया है कि दक्षिण भारत की लॉबी के अलावा शराब और रेस्तरां कारोबारी दिनेश अरोड़ा और आप (AAP) नेता और दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच की कड़ी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ही थे।

शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) से पहले किसी माध्यम से संजय सिंह को जब दिनेश अरोड़ा के बारे में पता चला था, तब उन्होंने उससे बात कर पार्टी के लिए फंड एकत्र करने का अनुरोध किया था। उसी के बाद 2020 में पहली बार दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा ने संजय सिंह के सरकारी आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी।

सिसोदिया से मुलाकात कराने से पहले संजय सिंह ने रखी थी ये शर्त

उनके बीच फंड एकत्र करने को लेकर घंटों चर्चा हुई थी। दिनेश अरोड़ा ने जब मनीष सिसोदिया और अन्य से परिचय कराने की मंशा जाहिर की, तब संजय सिंह ने उसके सामने शर्त रखते हुए कहा था कि वह पहले उनके कुछ खास लोगों को रेस्तरां और शराब के कारोबार में शामिल करें, उसके बाद उसकी मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराई जाएगी। शर्त मानते हुए अरोड़ा ने संजय सिंह के कुछ खास लोगों को अपने कारोबार में शामिल कर लिया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इन बातों का जिक्र किया है।

फिर शुरू हो गया बैठकों का दौर

आरोप पत्र में कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा को विवेक त्यागी से भी मिलवाया था। विवेक त्यागी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का करीबी है। धीरे-धीरे इनकी बैठकें होनीं शुरू हो गईं थी। एक बैठक में दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के अलावा सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी (संजय सिंह का निजी सचिव) और विवेक त्यागी भी शामिल हुए थे।

सिसोदिया से कैसे हुई मुलाकात

सजंय सिंह के घर अमित अरोड़ा की कई बार बैठक हुई थी। मनीष सिसोदिया से अरोड़ा की मुलाकात एक डाक्युमेंट्री तैयार करने की बात पर हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने-अपने लाभ की बातें साझा की थीं।

आबकारी नीति बनवाने में शामिल थे संजय सिंह

ईडी सूत्रों के अनुसार, सजंय सिंह, आबकारी नीति बनवाने में भी शामिल थे। जिसके लिए संजय सिंह को मोटा कमीशन मिलना था। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई आरोपितों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ में जो नए सुबूत मिले, ईडी ने सीबीआई को लिखित में उसकी जानकारी दी थी।

अगस्त 2022 में केस दर्ज, सितंबर में पहली गिरफ्तारी

ईडी के मुताबिक, दिनेश अरोड़ा के अलावा कई और लोगों ने संजय सिंह का नाम लिया है। वे सभी भी ईडी के जांच के दायरे में हैं। सीबीआई ने अगस्त 2022 में आबकारी घोटाला मामले में केस दर्ज किया था। पहली गिरफ्तारी सितंबर में विजय नायर की हुई थी। 25 नवंबर को सीबीआई ने पहली बार आरोप पत्र दायर किया था।

अगस्त 2022 में ईडी की हुई एंट्री

जांच में करोड़ों के लेनदेन की बात सामने आने के बाद ईडी ने 23 अगस्त 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी केस दर्ज कर लिया था। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीते 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद मार्च में ईडी ने अपने केस में उन्हें गिरफ्तार किया था।

अप्रैल में सीएम केजरीवाल से भी हुई पूछताछ

इससे माना जा रहा है कि ईडी की जांच पूरी होने के बाद संजय सिंह को सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है। बीते अप्रैल में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अब तक चार आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।

अब तक 22 आरोपी हुआ गिरफ्तार

ईडी संजय सिंह समेत 22 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। आबकारी घोटाला मामले में दक्षिण भारत की लॉबी के तीन लोगों ने कारोबारियों की तरफ से आप नेताओं से डील की थी, जिससे बाद 100 करोड़ रुपये आए थे, जिनमें 31 करोड़ रुपये दिनेश अरोड़ा ने हवाला के जरिये पार्टी नेताओं को गोवा चुनाव में खर्च करने के लिए भेजे थे।

आबकारी घोटाले के किरदार

विजय नायर (साउथ ग्रुप का सदस्य)
समीर महेंदू (इंडो स्प्रिट के मालिक)
अमित अरोड़ा (बद्दी रिटेल के मालिक)
राघव माटुंगा (साउथ ग्रुप का सदस्य)
पी शरत रेड्डी (अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर)
अभिषेक बोनापल्ली (साउथ ग्रुप का सदस्य)
बुची बाबु (के. कविथा के पूर्व सीए)
बेनाय बाबू (रिकॉर्ड इंडिया का क्षेत्रीय प्रमुख)
गौतम मल्होत्रा (अकाली दल के पूर्व विधायक दीपक मल्होत्रा का कारोबारी बेटा)
राजेश जोशी (डायरेक्टर चेरिटेबल प्रोडक्शन)

आबकारी केस के तीन सरकारी गवाह

दिनेश अरोड़ा (राधा इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर), राघव माटुंगा, शरत रेड्डी।

एलजी ने फर्जी दस्तावेजों से शिक्षकों की नियुक्ति मामले की CBI जांच के आदेश दिए, सभी को बर्खास्त भी किया

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सात शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया है।

दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सात शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया है। एलजी ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करने और भर्ती की प्रक्रिया को कारगर बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है। उधर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर होम में काम कर रहे 281 संविदा कर्मचारियों का वेतन जारी करने के आदेश दिए हैं। इन कर्मियों को पांच माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। कर्मी आशा किरण, आशा दीप और आशा ज्योति होम्स में बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों को बुनियादी दैनिक देखभाल प्रदान कर रहे हैं। इन कर्मियों में 221 हाउस आंटियां, देखभालकर्ता, 17 नर्स (जीएनएम), 34 नर्स (एएनएम), एक रसोइया, पांच रसोई सहायक, एक एलडीसी और दो ऑफिस का काम करने वाले लोग हैं। एलजी के आदेश पर इन कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक का वेतन जारी करने का आदेश दिया गया है।

लेखा परीक्षक को घर लेकर गए ठग, उनसे ही खुलवाया लॉकर...रुपये लेकर जाते समय कही ये बात

बदमाशों ने इस सफाई से वारदात को अंजाम दिया कि पीड़ित असली और नकली अधिकारी में फर्क नहीं कर पाए। कार से बदमाशों के भागने के बाद पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। उसके बाद पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की।

जहांगीरपुरी इलाके में इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर बदमाशों ने एक लेखा परीक्षक को ठग लिया। बदमाशों ने उनके टर्न ओवर जांचने के लिए एटीएम पर पीड़ित के बैंक खाते को खंगाला और फिर घर आकर एक लाख रुपये और मोबाइल लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने इस सफाई से वारदात को अंजाम दिया कि पीड़ित असली और नकली अधिकारी में फर्क नहीं कर पाए। कार से बदमाशों के भागने के बाद पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। उसके बाद पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने में जुटी है।

विवेक तलवार अपनी पत्नी अंजली के साथ जहांगीरपुरी में किराए के मकान में रहते हैं। मूलतः अमृतसर पंजाब के रहने वाले विवेक पेशे से लेखा परीक्षक हैं और घर से ही काम करते हैं। उनकी पत्नी भी कामकाजी हैं। पुलिस को दी शिकायत में विवेक ने बताया कि 4 अक्तूबर को सोनीपत जाने के लिए वह घर से जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात नंबर से उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वह इनकम टैक्स विभाग से बोल रहे हैं। साथ ही कहा कि उसने उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है और टर्न ओवर जांच करने की बात कहकर उन्हें जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बुलाया।

आरोप है कि जूस की दुकान के पास एक शख्स मिला। जिसमें खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताया। उसने पूछा कि बैंक खाते में कितने पैसे हैं। फिर वह उन्हें लेकर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर गया। जहां खाते के बैलेंस की जांच की। बैंक खाते में 74 रुपये थे। फिर उसने बैंक खाते की एक रसीद दिखाते हुए कहा कि इस खाते में 50 हजार रुपये दिखा रहा है। उसने कहा कि किसी से 50 हजार बैंक खाते में डलवाओ। फिर अचानक उसने पीड़ित को अपना घर दिखाने के लिए कहा। आरोपी उसे एक स्विफ्ट कार में बिठाया। जिसमें पहले से दो लोग सवार थे।

पीड़ित ने बताया कि उनकी कार में एक बैग रखा था, जिसमें काफी पैसे थे। इन लोगों ने पैसे दिखाकर कहा कि वह ठग नहीं बल्कि इनकम टैक्स अधिकारी हैं। उसके बाद सभी पीड़ित को लेकर उनके घर पहुंचे। कार में बैठे लोग घर के बाहर ही रहे, जबकि पहले वाला शख्स पीड़ित के साथ उनके घर गया। जहां उसने पीड़ित को विभाग का कार्ड दिखाया। फिर उसने घर में रखे पैसे दिखाने के लिए कहा। लॉकर की चाबी पत्नी के पास होने की वजह से पीड़ित ने फोन कर उन्हें घर बुलाया और फिर उसमें रखे एक लाख रुपये आरोपी को दिखाए।

राहुल गांधी के घर आया नन्हा मेहमान, सरप्राइज देख खिलखिला उठीं सोनिया गांधी; कांग्रेस सांसद ने शेयर किया वीडियो

केरल के वायानाड से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह अपने घर में आए नन्हे मेहमान के लिए सुर्खियों में हैं। इस मेहमान को देखकर पहली बार तो उनकी मां सोनिया गांधी बेहद डर गईं थीं लेकिन कुछ ही देर में वह सामान्य हो गईं और उसे खूब दुलारा और पुचकारा। यह नया मेहमान है एक छोटी डॉगी नूरी।

नई दिल्ली। केरल के वायानाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों लगातार अपनी यात्राओं लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी वह ट्रक चालकों के साथ सैर करते नजर आते हैं तो कभी वह डीयू के छात्रों से बातचीत करते नजर आते हैं।

कभी वह खेतों में धान की रोपाई करने पहुंच जाते हैं तो कभी वह दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में मेज बनाते दिख जाते हैं। इन सभी से वह लगातार चर्चा में बने रहते हैं। अब एक बार फिर वह अपने एक वीडियो के लिए सुर्खियों में हैं जिसमें उनके घर में नन्हा मेहमान आया है। इस मेहमान के आने से उनकी मां सोनिया गांधी भी बेहद खुश हैं।

राहुल के घर आई नन्ही नूरी

दरअसल यह नन्हा मेहमान कोई और नहीं उनकी छोटी पपी (कुत्ते का बच्चा) नूरी है। राहुल गांधी ने नूरी का वीडियो यूट्यूब पर डाला है। इसमें उन्होंने बताया है कि वह एक बार गोवा गए थे तब वह नूरी से मिले थे।

नूरी उनके पास गोवा से आई है। राहुल ने डॉगी को अपनी मां से छिपाकर मंगाया था और आने के बाद उन्होंने मां सोनिया गांधी को सरप्राइज दिया। सरप्राइज देखते ही सोनिया पहले डरीं, फिर खिलखिला उठीं और नूरी का खूब दुलार किया। दोनों ही नूरी के साथ बेहद खुश नजर आए।

पुराने डॉग को लेकर भी सुर्खियों में रहते थे राहुल

राहुल अपने डॉग लव को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। एक बार सोशल मीडिया पर जब किसी ने पूछा था उनके ट्वीट्स (अब एक्स पोस्ट) कौन करता है तो उन्होंने तंजिया लहजे में कहा था कि पिद्दी (उनका डॉगी) उनके ट्वीट्स करता है।

मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बड़े वकीलों पर अरविंद केजरीवाल ने 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

'आप' का क्या होगा: 'मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाले में मास्टर माइंड हैं, जल्द जांच के घेरे में आएंगे'

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल्द जांच के घेरे में आएंगे। सांसद ने कहा कि संजय सिंह के घर पर ही सभी शराब माफिया की बातचीत होती थी। इसके बाद संजय सभी को लेकर केजरीवाल के घर जाते थे। सांसद के मुताबिक ईडी ने कोर्ट को बताया है कि संजय दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से मिलते रहते थे। कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह के दो करोड़ लेने की बात की जानकारी दी है।

गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बड़े वकीलों पर अरविंद केजरीवाल ने 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि चुनाव के कारण भाजपा डर गई है, लेकिन ये बातें ईडी द्वारा जब संजय सिंह से सवाल पूछा जाएगा तो उस वक्त नहीं काम आने वाला है। उन्होंने केजरीवाल को जल्दी अपना गुनाह कबूल करने की सलाह देते हुए कहा कि इससे शायद उन्हें कम सजा मिलेगी।

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा लगाने वाले केजरीवाल आज लालू यादव के शागिर्द बने हुए हैं। उनका राजनीतिक धर्मांतरण देखकर हर कोई हैरान है। जब भी कोई गिरफ्तारी होती है, तो आम आदमी पार्टी के अंदर एक ही टेप रिकॉर्ड सुबह से शाम तक चलता रहता है लेकिन भाजपा द्वारा पूछे गए 15 सवालों का जवाब आज तक किसी भी आप नेता द्वारा नहीं दिया गया है। हम उनसे फिर वही अहम सवाल पूछते हैं। आखिर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी इंडो स्पीरिट से एक करोड़ रुपये लेने का मामला क्यों आया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में अगर कोई सबूत नहीं मिला है तो फिर मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने शराब घोटाले का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट क्यों बता दिया।

ग्रेप लागू होने के बाद से रोजाना बढ़ रहा प्रदूषण, सतर्क नहीं अधिकारी

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में ग्रेप लागू होने के बाद से रोजाना प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसे लेकर अधिकारी सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रांस हिंडन में बुधवार को जगह-जगह सड़कों पर धूल उड़ती मिली। पुराने वाहन से निकलने वाला धुआं प्रदूषण फैला रहा है। कई जगह कूड़ा जलता भी पाया गया। प्रदूषण बढ़ने से सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ रही है।

साहिबाबाद। ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस प्लान) लागू होने के बाद से रोजाना जिले का वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इससे सांस के मरीजों को परेशानी व विभिन्न बीमारियां होने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है।

अधिकारी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 200 के पार पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उपाय करने के बजाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के नियमों का हवाला दे रहे हैं।

एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए एक अक्टूबर से ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू हो चुका है। इसके अनुसार एक्यूआइ 200 के पार जाने पर ही कार्रवाई करने के आदेश हैं।

वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ने के बाद भी विभागीय अधिकारी अभी तक सक्रिय नहीं हुए हैं। एक से चार अक्टूबर तक एक्यूआइ 23 अंक बढ़ गया है। ट्रांस हिंडन में बुधवार को जगह-जगह सड़कों पर धूल उड़ती मिली। पुराने वाहन से निकलने वाला धुआं प्रदूषण फैला रहा है।

कई जगह कूड़ा जलता भी पाया गया। कनावनी पुस्ता रोड, अहिंसा खंड-दो, नीति खंड, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, जीटी रोड आदि पर दिनभर धुल उड़ती रही। जीडीए व नगर निगम की कोई गाड़ी छिड़काव करती नहीं दिखी। विभागों अपना काम नहीं कर रहे हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है।

अहिंसा खंड दो में कूड़े में जलता मिला

अहिंसा खंड दो में एक खाली प्लाट में पड़ा कूड़ा जलता मिला। इसके आस पास रेहड़ी लगाने वालों व वहां के लोगों से पूछा गया तो वह आग लगने का कारण नहीं बता पाए। इसी तरह कई जगह कूड़ा जलता पाया गया।

ग्रेप लागू होने के बाद पिछले चार दिन में बढ़ा जिले का एक्यूआई

दिनांक	एक्यूआई
चार अक्टूबर	180
तीन अक्टूबर	168
दो अक्टूबर	165
एक अक्टूबर	157

बुधवार को लोनी व वसुंधरा का एक्यूआइ 200 के पार पहुंचा

स्टेशन	एक्यूआइ
वसुंधरा	218
इंदिरापुरम	154
संजयनगर	137
लोनी	209

स्वास्थ्य पर प्रदूषण का कब कितना प्रभाव होता है?

एक्यूआई	श्रेणी	प्रभाव
0-50	अच्छा	कम प्रभाव
51-100	संतोषजनक	बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत
101-200	मध्यम	फेफड़े, अस्थमा व हृदय रोग से पीड़ितों को सांस लेने में दिक्कत
201-300	खराब	अधिकांश लोगों को सांस लेने में तकलीफ
301-400	बेहद खराब	लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन संबंधी बीमारी
401 से अधिक	आपात	स्वस्थ लोगों के साथ बीमारियों से ग्रस्त लोगों को गंभीर प्रभावित

जिन सड़कों पर धूल उड़ने की समस्या है उनकी सूची तैयार की जा रही है। सड़कों से संबंधित विभागों को पत्र जारी किया जाएगा। रोजाना छिड़काव कराना अनिवार्य है। इसके लिए एक्यूआइ 200 के पार जाने का इंतजार नहीं करना है।

-विकास मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी

नगर निगम की 10 गाड़ियां सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई गई हैं। जरूरत पड़ने पर टैंकरों के फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

-आनंद त्रिपाठी, जीएम, जलकल विभाग

नर्स से छेड़छाड़ कर मारी ईंट, आरोपितों संग पीड़िता का पिता का भी किया चालान

कान फोड़ू संगीत की आवाज धीमी करने को कहा तो पड़ोसियों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को पीटा। बचाने आई उनकी पोती से मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। अश्लील हरकत के विरोध पर उसे ईंट मार दी। घटना वेव सिटी क्षेत्र में चार अक्टूबर की रात की है। पीड़िता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांच में से दो हमलावरों के साथ उनके पिता को भी पकड़ लिया।

गाजियाबाद। संगीत की आवाज धीमी करने को कहा तो पड़ोसियों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को पीटा। बचाने आई उनकी पोती से मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। अश्लील हरकत के विरोध पर उसे ईंट मार दी। घटना वेव सिटी क्षेत्र में चार अक्टूबर की रात की है। पीड़िता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांच में से दो हमलावरों के साथ उनके पिता को भी पकड़ लिया और शांति भंग में चालान कर दिया।

पीड़िता का पड़ोसी बजाता रहता है तेज आवाज में गाने

डासना की एक कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता नर्स है और आगे की पढ़ाई कर रही हैं। पड़ोसी अशोक अपने घर पर आए दिन तेज आवाज में संगीत बजाता रहता है। उसकी बेटी के जन्मदिन के कारण चार अक्टूबर को भी तेज आवाज में गाने बज रहे थे।

बुजुर्ग की है तबीयत खराब

उनके दादा की तबीयत खराब है और तेज आवाज के कारण उन्हें परेशानी हुई तो आवाज धीमी करने को कहा। अशोक, उसका बेटा अमन, भाई हुकमा और भतीजे सचिन व मनीष ने दादा से मारपीट कर दी। शोर सुन वह आईं और दादा को बचाने की कोशिश में उनसे भी मारपीट की गई। पुलिस ने मारपीट का मामला बता दोनों पक्षों का चालान कर दिया, जबकि उनके पिता सिर्फ बचाने की कोशिश करते रहे।

एसीपी वेव सिटी सलोनी अग्रवाल का कहना है कि छेड़छाड़, बलवा व मारपीट के आरोप में पांचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे।

घर में खड़ी स्कूटी का कटा 25 हजार रुपये का चालान, पीड़ित व्यक्ति ने पकड़ी जालसाजी

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घर में खड़ी स्कूटी का चालाना होता रहा है। कई बार मिलाकर जब चालान 25 हजार का हो गया तो पीड़ित खुद ही स्कूटी को ढूंढ़ने लगा। उसने जागृति विहार में अपनी स्कूटी जैसी दूसरी देखी जिस पर नंबर भी उन्हीं का पड़ा था। स्कूटी के चालान अप्रैल 2023 से होने शुरू हुए।

गाजियाबाद। गाजियाबाद में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घर में खड़ी स्कूटी का चालाना होता रहा है। कई बार मिलाकर जब चालान 25 हजार का हो गया तो पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी।

उसी नंबर की देखी दूसरी स्कूटी

चालान का जुर्माना 25 हजार रुपये पहुंच गया तो पीड़ित परेशान हुआ और खुद ही स्कूटी को ढूंढ़ने लगा। पिछले दिनों उन्होंने जागृति विहार में अपनी स्कूटी जैसी दूसरी देखी, जिस पर नंबर भी उन्हीं का पड़ा था तो पुलिस को सूचना दी।

अप्रैल 2023 से शुरू हुए चालान कटने

रईसपुर में रहने वाले नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूटी के चालान अप्रैल 2023 से होने शुरू हुए। शुरुआत में उन्होंने अंदेखा किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आए दिन कभी गलत दिशा तो कभी बिना हेलमेट में चालान हुए, जिनका जुर्माना 25 हजार हो गया तो वह पुलिस के पास पहुंचे थे।

चोरी की निकली दूसरी बरामद स्कूटी

एसीपी कवि नगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि नरेंद्र का नंबर पड़ी स्कूटी कब्जे में ले ली है। यह स्कूटी मोहम्मद रफीक के पास मिली थी। रफीक ने रईसपुर के मुकुल से स्कूटी खरीदी थी। जानकार होने के चलते उन्होंने भरोसा कर लिया। उसने बाद में दस्तावेज देने को कहा था, जो नहीं दिए। रफीक ने मुकुल को ऑनलाइन भुगतान किया था। बरामद स्कूटी कवि नगर क्षेत्र से चोरी होने की बात सामने आई है। मुकुल को पुलिस तलाश रही है।

पुलिस की गाड़ी को रोककर लूटने की कोशिश, तीन बदमाश गिरफ्तार

गुरुग्राम के मार्बल मार्केट में बुधवार रात हथियार के साथ लूट के इरादे से खड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीन बदमाशों ने दबोच लिया है। बदमाशों ने आमजन की गाड़ी समझकर पुलिस की गाड़ी को ही रोककर लूटने का प्रयास किया। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल एक कारतूस लोहे की पाइप व टार्च बरामद की है।

गुरुग्राम। सेक्टर 34 के मार्बल मार्केट में बुधवार रात हथियार के साथ लूट के इरादे से खड़े होने की सूचना पर सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। बदमाशों ने आमजन की गाड़ी समझकर पुलिस की गाड़ी को ही रोककर लूटने का प्रयास किया। पुलिस ने तीनों आरोपितों को धर दबोचा।

पुलिस की गाड़ी रुकवाकर लूटने की कोशिश

सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर पंकज ने बताया कि उनकी टीम को सूत्रों से मार्बल मार्केट में हथियार के साथ कुछ लोगों के खड़े होने की जानकारी मिली थी। आरोपितों को पकड़ने के लिए विशेष योजना बनाकर पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई। यहां तीनों आरोपितों ने पुलिस टीम की गाड़ी को आमजन की गाड़ी समझकर रुकवाया व हथियार के बल पर लूटने का प्रयास किया।

पुलिस की बिछाए जाल में फंस गए आरोपी

पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से पहले से बिछाए जाल में तीनों आरोपितों को पकड़ लिया। इनकी पहचान नूंह के चहलका निवासी नसीम खान, नोमान व गांव पीपाका निवासी असलम के रूप में की गई। सदर थाने में आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है।

तेलंगाना में चार बार एटीएम में गड़बड़ी कर निकाले लाखों रुपये

प्रारंभिक पूछताछ में तीनों आरोपितों ने तेलंगाना के खमम जिले में एटीएम मशीन में गड़बड़ी कर 12 लाख रुपये निकालने की चार वारदात का पर्दाफाश किया। आरोपित असलम पर चोरी के दो मामले नूंह के तावडू में दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, एक कारतूस, लोहे की पाइप व टार्च बरामद की है। तीनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया।

मुसलमानों में भी जाति आधारित गणना होनी चाहिए, वहां भी भयंकर जातिवाद है

बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से यूपी में भी जातीय जनगणना कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी पहले से ही ओबीसी को हक दिलाने के लिए मुखर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तो हर समय जातीय जनगणना का राग अलापते रहते हैं।

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना के मसले पर सियासत शुरू हो गई है। योगी सरकार पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी विरोधी नेता और गठबंधन तो हो-हल्ला मचा ही रहे हैं। भाजपा के सहयोगी दलों के नेता भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना मसले पर भले ही योगी सरकार और बीजेपी अलग-थलग पड़ गई हो, लेकिन वह विरोधियों के सामने 'हथियार' डालने को तैयार नहीं हैं। फिर भी इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी जातीय जनगणना की वकालत करने वालों को भले ही हिन्दू एकता के लिए खतरा बता रही हो, लेकिन बेचैनी उसकी भी बढ़ी हुई है क्योंकि यह वह आग है जिसमें सबका 'झुलसना' तय है। इस आग में कौन अपनी सियासी रोटियां सेंकने में सफल होगा, यह समय बतायेगा। परंतु यह भी तय है कि इसका फैसला चंद महीनों के भीतर होने वाले तीन राज्यों के विधान सभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव हो जायेगा। लेकिन काट हर चीज की होती है, इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि जातीय जनगणना की मांग को हवा देकर किसी पार्टी का सियासी सफर थम जायेगा या फिर उसका ग्राफ बेतहाशा बढ़ जायेगा। बिहार में इसकी बानगी दिखने भी लगी है, वहां पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार कैसे इतने लम्बे समय से सीएम बने हुए हैं, जबकि बिहार में उनकी कुर्मी जाति की भागेदारी मात्र दो-ढाई प्रतिशत ही है। इसी प्रकार लालू यादव के परिवार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि बिहार में यादवों की भागीदारी मात्र 14.27 फीसदी हैं, लेकिन यह परिवार बिहार में लम्बे समय से राज कर रहा है। क्यों नहीं लालू या नीतीश की पार्टी द्वारा 19.65 भागीदारी वाले दलित नेता को सीएम नहीं बनाया जाता है? इसी प्रकार 17.70 फीसदी मुसलमानों में से किसी को अभी तक सीएम की कुर्सी क्यों नहीं नसीब हुई? बीजेपी सवाल खड़ी कर रही है कि क्यों लालू और नीतीश ही हर बार उनकी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा होते हैं।

बहरहाल, जातीय जनगणना की सियासत में पिछड़ों को सियासी फायदा जरूर हो सकता है क्योंकि एक अनुमान के अनुसार यूपी में कुल जनसंख्या में पिछड़ों की आबादी करीब 60 फीसदी से अधिक बताई जाती है। हालांकि 1931 की जनगणना के बाद ओबीसी आबादी के जातिवार विभाजन का कोई प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं था, लेकिन 2001 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राजनाथ सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री हुकुम सिंह की अगुवाई वाली समिति ने राज्य में 79 ओबीसी की आबादी के आधार पर 7.56 करोड़ की गणना की थी। ऐसे में पिछड़ा समाज के वोटरों को लुभाने के लिए कई दल अधिक संख्या में पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकते हैं। मगर यह सब इतना आसान नहीं होगा। इसी मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से यूपी में भी जातीय जनगणना कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी पहले से ही ओबीसी को हक दिलाने के लिए मुखर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तो हर समय जातीय जनगणना का राग अलापते रहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी के जो नेता जातीय जनगणना के लिए हायतौबा मचा रहे हैं उनकी यूपी में लम्बे समय तक अपनी सरकारें रह चुकी हैं, परंतु तब इन्हें जातीय जनगणना कराये जाने की जरूरत नहीं लगी। पर अब सबके ऊपर जातीय जनगणना का भूत सवार है। खास बात यह है कि यह नेता हिन्दुओं की कुल आबादी में कितने प्रतिशत दलित, पिछड़े और अगड़े हैं, इसकी तो गणना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों में कितने अगड़े-पिछड़े हैं, इसका पता लगाना यह जरूरी नहीं समझते हैं। जबकि हिन्दुस्तान में मुसलमानों के बीच भी ठीक वैसे ही जातिवाद का जहर फैला हुआ है, जैसे हिन्दुओं में फैला है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लालच में कुछ नेताओं को यह दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुसलमानों में जाति के आधार पर कोई भेद ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमानों में भी जातियां तो हैं, लेकिन उनमें उतने गंभीर मतभेद हैं नहीं, जितना कि हिंदुओं में हैं। मुसलमानों में जातिवादी भेदभाव की बात की जाए तो भारतीय मुसलमान मुख्यतः तीन जाति समूहों में बंटा हुआ है। इन्हें अशराफ, अजलाफ और अरजाल कहा जाता है। ये जातियों के समूह हैं, जिसके अंदर अलग-अलग जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं, वैसे ही अशराफ, अजलाफ और अरजाल को देखा जाता है। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पसमांदा मुस्लिम आंदोलन के नेता अली अनवर अंसारी कहते हैं कि अशराफ में सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल जैसी उच्च जातियां शामिल हैं। मुस्लिम समाज की इन जातियों की तुलना हिंदुओं की उच्च जातियों से की जाती है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हैं।

दूसरा वर्ग है अजलाफ। इसमें कथित बीच की जातियां शामिल हैं। इनकी एक बड़ी संख्या है, जिनमें खास तौर पर अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी जैसी कई जातियां शामिल हैं। कुरैशी मीट का व्यापार करने वाले और अंसारी मुख्य रूप से कपड़ा

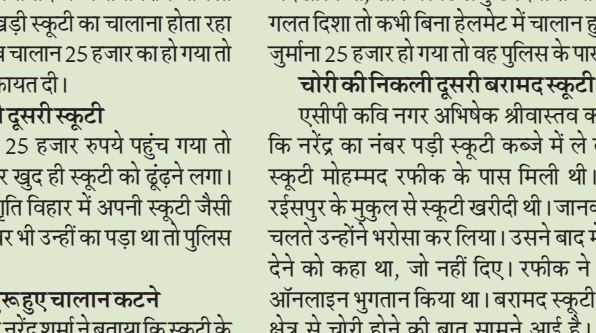

बुनाई के पेशे से जुड़े होते हैं। हिंदुओं में उनकी तुलना यादव, कोइरी, कुर्मी जैसी जातियों से की जा सकती है। तीसरा वर्ग है अरजाल। इसमें हलालखोर, हवारी, रज्जाक जैसी जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में मैला ढोने का काम करने वाले लोग मुस्लिम समाज में हलालखोर और कपड़ा धोने का काम करने वाले धोबी कहलाते हैं। इन मुसलमान जातियों का पिछड़ापन आज भी हिंदुओं की समरूप जातियों जैसा ही है। मुसलमानों में भी जाति प्रथा हिंदुओं की तरह ही काम करती है। विवाह और पेशे के अलावा मुसलमानों में अलग-अलग जातियों के रीति रिवाज भी अलग-अलग हैं। मुसलमानों में भी लोग अपनी ही जाति देखकर शादी करना पसंद करते हैं। मुस्लिम इलाकों में भी जाति के आधार पर कॉलोनियां बनी हुई दिखाई देती हैं। कुछ मुसलमान जातियों की कॉलोनी एक तरफ बनी हुई है, तो कुछ मुसलमान जातियों की दूसरी तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में तुर्क, लोधी मुसलमान रहते हैं। उनके बीच काफी तनाव रहता है। उनके अपने-अपने इलाके हैं। राजनीति में भी ये देखा जाता है। इस संबंध में राज्यसभा सांसद रहे अली अनवर अंसारी कहते हैं कि जीने से लेकर मरने तक मुसलमान जातियों में बंटा हुआ है। शादी तो छोड़िए, एक-दो अपवादों को छोड़कर इनके बीच रोटी-बेटी का रिश्ता भी नहीं है। जाति के आधार पर कई मस्जिदें बनाई गई हैं। गांव-गांव में जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान बनाए गए हैं। हलालखोर, हवारी, रज्जाक जैसी मुस्लिम जातियों को सैयद, शेख, पठान जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं दी जाती। उनके अनुसार, कई बार तो पुलिस को बुलाना पड़ता है। अक्सर मुसलमान जातीय आधार पर आरक्षण की मांग भली करते रहते हैं, लेकिन अपनी राजनीति बचाये रखने के लिए तमाम नेताओं को यहां कुछ गलत और जातिवाद नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही सवाल यूपी में मायावती, अखिलेश और कांग्रेस के समाने भी खड़े हो सकते हैं क्योंकि यह लोग भले ही सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना की बात करते हों, लेकिन चुनाव जीतने पर स्वयं सीएम की कुर्सी पर चिपक कर बैठ जाते हैं और अपने करीबियों को अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठा देते हैं। यहां तक की नौकरशाही भी इन नेताओं के जातिवादी रंग में रंग जाती है।

बात उत्तर प्रदेश की कि जाए तो यूपी में जनसंख्या में 55 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी ओबीसी की होगी। राजनाथ सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2001 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश की पिछड़ी जातियों में सर्वाधिक 19.4 प्रतिशत हिस्सेदारी यादवों की हैं। दूसरे पायदान पर कुर्मी व पटेल हैं, जिनकी ओबीसी में 7.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ओबीसी की कुल संख्या में निषाद, मल्लाह और केवट 4.3 प्रतिशत, भर और राजभर 2.4 प्रतिशत, लोध 4.8 प्रतिशत और जाट 3.6 प्रतिशत हैं। हुकुम सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रदेश की 79 अन्य पिछड़ी जातियों की आबादी 7.56 करोड़ होने का अनुमान लगाया था। यह आकलन ग्रामीण क्षेत्रों में रखे जाने वाले परिवार रजिस्टरों के आधार पर किया गया था। यह मानते हुए कि नगरीय क्षेत्रों की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 20.78 प्रतिशत है, वर्ष 2001 में उप्र में ओबीसी की संख्या राज्य की 16.61 करोड़ की कुल आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक रही होगी। हुकुम सिंह समिति ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने पर ओबीसी को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण के भीतर अति पिछड़ी जातियों (एमबीसी) के लिए आरक्षण के मुद्दों पर गौर किया था। बता दें कि इससे पहले मंडल आयोग ने देश की कुल जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी 52.2 प्रतिशत मानी थी।

अति पिछड़ी जातियों को लेकर राजनीति गर्माने तथा ओबीसी कोटे के अंदर अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए उठी मांग के परिप्रेक्ष्य में योगी सरकार ने वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति राघवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में एक और सामाजिक न्याय समिति गठित करने का निर्णय किया। इस समिति ने अक्टूबर 2018 में 400 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें ओबीसी को तीन श्रेणियों में बांटा गया था।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों की संख्या में उछाल

ईवी बिक्री 20% बढ़ी और सरकार का रेवेन्यू 11% बढ़ा

राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनो की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी देखी गई है. 2023-24 की पहली दो तिमाही में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स से दिल्ली का रेवेन्यू कलेक्शन में 11% की वृद्धि हुई है.

नई दिल्लीः सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर फोकस कर रही है और कंपनियों को फेम स्कीम के तहत निर्माण में सब्सिडी दे रही है तो ग्राहकों को भी सब्सिडी का लाभ मिल रहा है. वहीं, पर्यावरण संरक्षण और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन बड़े स्तर पर लोगों के सामने आए हैं. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों की संख्या में तेज उछाल दर्ज किया गया है, जबकि ईवी सेल्स में 20% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की शुरुआती छमाही के दौरान दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि की तुलना में 20% बढ़ गई. आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहन लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, डीजल से चलने वाले वाहनों में रुचि कम हो रही है, जिसकी बिक्री में पिछले वित्तीय वर्ष के समान महीनों की तुलना में इस साल अप्रैल और सितंबर के बीच 24% से अधिक की कमी देखी गई है.

इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक राजधानी दिल्ली में 3,06,135 नए वाहन कार, बाइक और स्कूटर और कमर्शियल वेहिकल रिजस्टर्ड किए गए. जबकि, पिछले साल इसी अवधि में 2,94,305 थे. वाहनों की जिस कैटेगरी ने उपभोक्ताओं का सर्वाधिक ध्यान खींचा है वह इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) है. इस साल 30 सितंबर तक दिल्लीवासियों ने 32,400 ईवी खरीदीं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 26,936 था. इस बार 1 अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि के दौरान रजिस्टर्ड डीजल वाहनों की संख्या पिछले साल के 8,393 से घटकर 6,344 हो गई है.

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि कार डीलरों के फीडबैक से पता चला है कि उपभोक्ता इलेक्ट्रिक वाहनों के नए मॉडल और वेरिएंट की तलाश कर रहे हैं, जबकि डीजल से चलने वाली कारों में रुचि कम हो रही है. लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया है कि डीजल से चलने वाली कारें न केवल महंगी हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी कम अनुकूल हैं. यही कारण है कि इलेक्ट्रिक कारें और बाइक अब अधिक लोकप्रिय हो रही हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगस्त 2020 में तीन साल की अवधि के लिए पेश किया गया था, हाल ही में छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है. 2025 तक सभी रजिस्टर्ड नए वाहनों में 25% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है. इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच दिल्ली में रजिस्टर्ड कुल वाहनों में से लगभग 11% इलेक्ट्रिक थे. 2023-24 की पहली दो तिमाहियों में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स से दिल्ली का रेवेन्यू कलेक्शन 1,404 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो कि इसी अवधि में पिछले वित्त वर्ष की कमाई 1,268 करोड़ की तुलना में लगभग 11% की

ऑफरोडिंग से लेकर सड़कों पर फर्राटा भरते समय काम आते हैं ये फीचर्स, जानिए इनकी अहमियत

आज हम आपको कार में मौजूद कुछ फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको नॉर्मल रोड पर तो मदद करते ही करते हैं इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी मदद करते हैं। एक्सीडेंट होने पर एयरबैग पलक झपकते ही तेजी रफ्तार से खुल जाता है। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम कार की स्पीड ब्रेक पर लगने वाले फोर्स जैसी चीजों को मॉनिटर करता रहता है।

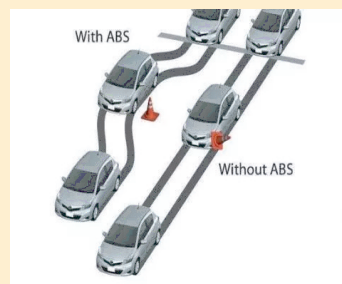

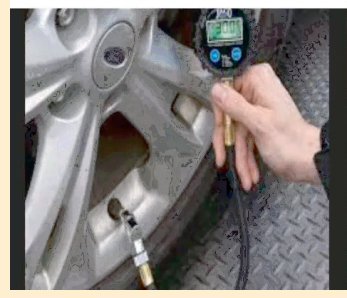

नई दिल्ली। कभी भी लॉन्ग वीकेंड बनता है तो लोग अक्सर पहाड़ों पर अपनी छुट्टियों का मजा लेने चले जाते हैं। क्या आप भी इस बार अपने लॉन्ग वीकेंड पर कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अगर आप अपनी कार से ही पहाड़ी सड़कों पर जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जिसके कारण आपका सफर अधिक सुरक्षित और यादगार बन जाएगा। ये फीचर्स आपको नॉर्मल रोड पर तो मदद करते ही करते हैं साथ में पहाड़ी इलाकों में भी मदद करते हैं।

एयरबैग

कार में एयरबैग सबसे जरूरी फीचर में से एक है, क्योंकि एक्सीडेंट होते ही ये एक्टिव हो जाता है और ड्राइवर के साथ-साथ पैसेंजर की भी जान बचाता है। एक्सीडेंट होने पर एयरबैग पलक झपकते ही तेजी रफ्तार से खुल जाता है और आपको सुरक्षित रखता है भारत में कई गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें एयरबैग मिलते हैं।

एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम

आज के समय में लॉन्च होने वाली सभी कारों में एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। क्योंकि यह कार में सबसे जरूरी फीचर में से एक है। इसके कारण कार की स्पीड ब्रेक पर लगने वाले फोर्स जैसी चीजों को मॉनिटर करता रहता है। कई बार ऐसा होता है जब अचानक से कार पर ब्रेक लगाना होता है तो ऐसे में यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कर को तेज स्पीड में ब्रेक लगाने पर कंट्रोल करता है इसके कारण फिसलन भरी सड़कों और तीखे मोड़ों पर आपको दिक्कत नहीं होती।

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

आज के समय में अधिकतर कारों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया जाता है। इसके कारण कार चलना काफी आसान हो जाता है। क्योंकि यह आपकी कार के हर टायर का एयर प्रेशर मॉनिटर करता रहता है। कई बार ऐसा होता है जब आप तेज स्पीड में कार चला रहे होते हैं और अचानक से टायर पंचर हो जाता है या फट जाता है। जिसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है लेकिन अगर आपके कार में यह फीचर रहता है तो आप इन सब से बच सकते हैं आपको पहले ही पता चल जाएगा आपके टायर में एयर प्रेशर कम है या फिर कितना है।

पिछले महीने इन कंपनियों ने बेचीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां

हाल ही में टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अलग प्लेटफार्म Tata.ev की शुरुआत कर दी है. जिसके तहत कंपनी तीन इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करती है. जिनके साथ पिछले महीने टाटा ने 4,613 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की. जोकि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है.

दूसरे नंबर पर एमजी मोटर्स है, जिसने पिछले महीने अपनी 1,150 यूनिट्स इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की और सेकंड नंबर पर रही. एमजी भारत में अपनी दो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करती है. जिनमें पहली सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार एमजी कॉमेट और दूसरी एमजी जेडएस ईवी.

पिछले महीने इन कंपनियों ने बेचीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां

तीसरे नंबर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा रही, जिसने 376 यूनिट्स इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की. महिंद्रा के पास फिलहाल इकलौती इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा एक्सयूवी400 है.

चौथे नंबर पर हुंडई की आयोनिक 5 और कोना इलेक्ट्रिक कार रही. कंपनी इनके 182 यूनिट्स की बिक्री करने में कामयाब रही.

पांचवे नंबर पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री करने वाली कंपनी सिट्रोएन बनी. जिसने पिछले महीने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार सिट्रोएन ईसी3 के 111 यूनिट्स की बिक्री की.

Pure EV ने लॉन्च किया 201KM रेंज वाला ePluto 7G Max इलेक्ट्रिक स्कूटर, रिवर्स मोड के साथ मिलते हैं ये फीचर्स

Pure EV E Pluto 7G Max electric scooter जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है। ये एक रेट्रो थीम वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसके अलावा ईवी इसमें कई दमदार फीचर्स भी मिलते हैं।इसमें मैट ब्लैक लाल ग्रे और सफेद कलर ऑप्शन मिलता है।इस स्कूटर को पावर देने के लिए 3.5 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक है। जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है।

दिल्ली। भारतीय बाजार में प्योर ईवी ने 114,999 (एक्स-शोरूम) कीमत पर ईप्लूटो 7जी मैक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर की बुकिंग पूरे देश में ओपन है और इसकी डिलीवरी वाहन निर्माता कंपनी त्योहारी सीजन से शुरू करेगी। ये एक रेट्रो थीम वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस ईवी के लॉन्च के साथ कंपनी का लक्ष्य अपनी ब्रिकी संख्या को बढ़ाना है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं।

E Pluto 7G Max

बिल्कुल नया ePluto 7G Max इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 201 किमी की रेंज देने का दावा करती है। इसके अलावा, ईवी इसमें कई दमदार फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें हिल-स्टार्ट असिस्ट, डाउनहिल असिस्ट, कोस्टिंग रीजेन, रिवर्स मोड, बैटरी लंबे समय तक चलने के लिए स्मार्ट एआई जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार अलग-अलग ऑप्शन भी आते हैं। इसमें मैट ब्लैक , लाल, ग्रे और सफेद कलर ऑप्शन मिलता है।

E Pluto 7G Max बैटरी पैक

इस स्कूटर को पावर देने के लिए 3.5 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है। जो 3.21 bhp की पीक पावर देता है। इसमें AIS-156 प्रमाणित बैटरी पैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस स्मार्ट बैटरी मिलता है। राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए इसमें तीन राइडिंग मोड भी मिलते हैं। इसके साथ ही ये ईवी स्कूटर 60,000 किलोमीटर की मानक बैटरी वारंटी के साथ आता है और 70,000 किलोमीटर की वारंटी भी मिलती है।

E Pluto 7G Max डिजाइन

ePluto 7G Max के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन पुराने स्कूल का डिजाइन है जो आज के समय के फीचर्स से लैस है। इसमें LED लाइट्स, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। जो स्मार्ट रीजेनरेटिव तकनीक से लैस है। इतना ही नहीं इसमें रिवर्स मोड असिस्ट भी मिलता है और पार्किंग असिस्ट भी मिलता है। जो राइडर की सुविधा को बढ़ाता है।

वो कौन-से कारण हैं जिसके चलते देश में जाति आधारित गणना के पक्ष में नहीं है भाजपा?

नीरज कुमार दुबे

जहां तक भाजपा के इस पर आधिकारिक रुख की बात है तो वह बहुत संभल कर चल रही है लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसके दबाव के चलते एक दिन आयेगा जब भाजपा जाति आधारित जनगणना का समर्थन करेगी।

देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडी के नेता अपनी रैलियों, सभाओं, संवाददाता सम्मेलनों और सोशल मीडिया पोस्टों के जरिये केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गणना करवाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है और सबसे बड़ी आबादी भी गरीब की ही है तथा उनकी सरकार अपनी हर नीति के केंद्र में इस वर्ग को रखती है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। जहां तक जातिगत गणना के मुद्दे पर मोदी सरकार के आधिकारिक रुख की बात है तो वह अदालत में तभी स्पष्ट हो गया था जब सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि जनगणना करते समय अन्य पिछड़ी जातियों की गणना नहीं की जाएगी।

दरअसल उस समय तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह जनगणना में पिछड़ी जातियों की भी गणना करे। महाराष्ट्र की तत्कालीन शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का तर्क था कि 2011 की जनगणना में तत्कालीन सरकार ने एक आयाम जोड़ा था, जिसके अंतर्गत जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। सरकार ने वे आंकड़े उस वक्त जाहिर नहीं किए थे लेकिन उन्हें अब जारी किया जाना चाहिए। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के उस तर्क का विरोध करते हुए मोदी सरकार ने अदालत से कहा था कि उस समय इकट्ठे किए गए आंकड़े इतने अजीबो-गरीब थे कि उन्हें जाहिर करना उचित नहीं होगा।

जहां तक भाजपा के इस पर आधिकारिक रुख की बात है तो वह बहुत संभल कर चल रही है लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसके दबाव के चलते एक दिन आयेगा जब भाजपा जाति आधारित जनगणना का समर्थन करेगी। वैसे यहां सवाल उठता है कि भाजपा आखिर क्यों नहीं चाहती कि जाति के आधार पर जनगणना हो? जबकि देखा जाये तो अन्य कारणों के अलावा, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा की प्रचंड जीत अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के मतदाताओं के बीच बनाई गई महत्वपूर्ण पैठ के कारण ही संभव हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा को अन्य जातियों या समुदायों से समर्थन नहीं मिला था। भाजपा अपने पारंपरिक समर्थकों, उच्च जातियों और उच्च वर्गों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के अलावा बड़ी संख्या में दलितों और आदिवासियों के मतों को जुटाने में भी कामयाब रही थी। इसलिए यह सवाल उठता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जाति-आधारित जनगणना कराने के बारे में अनिच्छुक क्यों लगती है?

जरा हालिया राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो बहुत कुछ समझ आ जायेगा। दरअसल 1990 के दशक की शुरुआत में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था जिसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। इस फैसले ने भारत में चुनावी राजनीति की प्रकृति को बदल कर रख दिया था, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में इसका बड़ा असर हुआ था। मंडल के बाद की राजनीति के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और वह मजबूत होकर राज्यों में अपनी जड़ें जमाने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके मजबूत उदाहरण हैं।

हम आपको बता दें कि 90 के दशक की शुरुआत में भाजपा को अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते ₹कमंडल राजनीति₹ के नाम से जाना जाता था। उस समय कमंडल को मंडल राजनीति का मुकाबला करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा था। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा तमाम नेताओं के नेतृत्व में कड़ी मेहनत की और दो सांसदों वाली यह पार्टी केंद्र की सत्ता तक पहुँचने में तभी सफल रही जब उसे पिछड़ों और अति पिछड़ों का भरपूर समर्थन मिला। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव परिणाम इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

उस समय भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन कर केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई और अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को किनारे रखकर एनडीए के साझा एजेंडे को आगे बढ़ाया। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि उस समय भले भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी लेकिन दोनों चुनावों में सर्वाधिक लाभ में क्षेत्रीय दल ही रहे थे। क्षेत्रीय दलों को 1998 में 35.5% और 1999 में 33.9% वोट मिले थे। यहां तक कि जब 2004 और 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने सरकार बनाई, तब भी क्षेत्रीय दलों को कुल मिलाकर 39.3% वोट मिले। क्षेत्रीय दलों को 2004 के लोकसभा चुनावों में 39.3% और 2009 के लोकसभा चुनावों में 37.3% वोट मिले थे। यहां तक कि जब भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान 31% वोटों के साथ बहुमत हासिल किया, तब भी क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर 39% वोट हासिल किए थे।

इसके अलावा, एक बड़ा आंकड़ा यह भी दर्शाता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पैठ बढ़ाई थी, जिससे क्षेत्रीय दलों के मूल समर्थन में ही सेंध लग गई थी जिससे उनका वोट शेयर घटकर 26.4% रह गया था। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि भाजपा ने पिछले एक दशक के दौरान ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पैठ बढ़ाई है। आंकड़ों के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनावों में 22% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि 42% ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया। लेकिन एक दशक के भीतर खासकर ओबीसी नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में उभार के बाद इस समुदाय का समर्थन भाजपा के साथ जुड़ गया जिससे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 44% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि केवल 27% ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया था।

लेकिन ओबीसी वर्ग के भाजपा को प्रचंड समर्थन के बावजूद मामले में एक पेंच है। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान तो ओबीसी मतदाताओं को भाजपा पसंद आती है लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की हो तो उनकी पसंद बदल भी जाती है। आंकड़ों के जरिये समझाने के लिए आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में केवल 11% ओबीसी ने राजद को वोट दिया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी ने राजद को वोट दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 14% ओबीसी ने ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था।

बहरहाल, जहां तक भाजपा की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना से बचने की बात है तो इसका एक प्रमुख कारण यह भी लगता है कि इस कवायद के चलते विभिन्न जातियों, विशेषकर ओबीसी जातियों के बारे में जो आंकड़े सामने आएंगे उससे क्षेत्रीय दलों को भाजपा पर दबाव बनाने के लिए नये मुद्दे मिल जाएंगे। यदि आंकड़े ऐसे आये कि केंद्र सरकार को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी कोटा को नया स्वरूप देना पड़ा तो इसके परिणामस्वरूप मंडल-2 जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इससे क्षेत्रीय दलों को नया जीवनदान मिल जायेगा। इसके अलावा कई दल ऐसे भी हैं जो भाजपा को राज्यों और केंद्र में चुनौती देने के लिए तमाम प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं लेकिन यदि जातिगत आंकड़े सामने आ गये तो वह भाजपा को आसानी से घेर सकते हैं। भाजपा के पास इस समय ओबीसी के सबसे ज्यादा विधायक और सांसद भले हों लेकिन पार्टी कतई नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना करवा कर ऐसे मुद्दे को हवा दी जाये जिसको संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आज का भाजपा नेतृत्व 90 के दशक की मंडल-कमंडल राजनीति से भलीभांति वाकिफ भी है। वह जानता है कि अटल-आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या-क्या प्रयास करने पड़े थे और कैसे-कैसे दिन देखने पड़े थे इसलिए अब जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत का पालन करते हुए राजनीति की जा रही है।

संपादक की कलम से

'महाभूकंप' की पदचाप

मंगलवार, 3 अक्तूबर, की दोपहर में अचानक धरती कांप उठी और हम लडख़ड़ा कर गिरते-गिरते बचे। तुरंत एहसास हो गया कि यह भूकंप का झटका था। सभी अपना काम यथावत छोड़ कर घर-दफ्तर के बाहर निकल गए, लेकिन उस दिन पृथ्वी के भीतर ऐसी हलचलें हुईं कि आधा घंटे के अंतराल पर दो भूकंप आए। बाद वाले भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। नेपाल का हिमालयीय क्षेत्र भूकंप का केंद्र था, लेकिन राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों ने कंपन और धक्के महसूस किए। भूकंप की यह तीव्रता भी खतरनाक और घातक है। ईश्वर की कृपा रही कि कहीं से जान-माल की त्रासद खबरें नहीं आईं। कुछ लोग नेपाल में घायल हुए हैं और एक पुराने भवन की दीवार ढही है। बहरहाल भूकंप विशेषज्ञ बार-बार आकलन करते हुए भविष्यवाणी करते रहे हैं कि ये भूकंप किसी 'महाभूकंप' की पदचाप हैं। ऐसा 'महाभूकंप' 50,100 या 200 सालों में कभी भी आ सकता है। उसके निश्चित समय का आकलन विशेषज्ञ भी नहीं कर पा रहे हैं। यदि 'महाभूकंप' आया, तो 'महाप्रलय' के हालात बनेंगे और तबाही, त्रासदियां व्यापक स्तर पर होंगी। तुर्किये के भूकंप संभावित महाप्रलय की बानगी माने जा सकते हैं। यदि भूकंप की तीव्रता 7 को पार कर गई और करीब 8 हुई, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की आधे से अधिक इमारतें वे भूकंपीय कंपन झेल नहीं पाएंगी। इसी साल अगस्त में 6 तीव्रता से अधिक के भूकंप हमने आधा दर्जन बार महसूस किए हैं। अलबत्ता भूकंपों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सवाल यह नहीं है कि भूकंप क्यों आते हैं या पृथ्वी के भीतर की प्लेटें आपस में क्यों टकराती हैं? ये सवाल फिलहाल हमारे वैज्ञानिक, भूगर्भीय विशेषज्ञों के अनुसंधान से परे हैं, लेकिन बुनियादी चिंता यह है कि हम लगातार भूकंपों से कांपने, हिलने-डुलने के बावजूद लापरवाह हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर अनिल गुप्ता का विश्लेषण है कि राजधानी दिल्ली की सोसायटियों में बहुमंजिला इमारतें बनी हैं। छोटे स्तर पर बिल्डर भी ऐसे भवन बनवा रहे हैं। वे भवन भूकंप-रोधी तकनीक से बन रहे हैं अथवा नहीं, इमारतों की भूकंप झेलने की क्षमताएं शेष हैं या नहीं, लंबे समय तक गर्मी, धूप, बारिश सहते हुए इमारतों पर उनके क्या प्रभाव पड़े हैं अथवा इमारतों के नीचे पानी रिस रहा है, तो सीलन कितनी है, इन तमाम स्थितियों की न तो उचित और निरंतर जांच की जाती है और न ही कोई कड़े कायदे-कानून हैं। यकीनन भूकंप के झटके हमारे निर्माणों की मजबूती को कमजोर तो कर ही रहे हैं। राजधानी दिल्ली की ही चिंता नहीं है, बल्कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उप्र, बिहार के कई हिस्से, गुजरात का कच्छ रण, सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडेमान-निकोबार द्वीप समूह आदि भूकंप-संवेदी क्षेत्र हैं। इन्हें जोन 4 और 5 में वर्गीकृत किया गया है। यानी ये क्षेत्र विध्वंस और मौत के कगार पर स्थित हैं। नेपाल का 7.9 तीव्रता वाला भूकंप 2015 में हम देख-पढ़ चुके हैं। कितने लोग मारे गए थे और कितने भवन 'मलबा' हो गए थे। इतिहास में 1897 का शिलांग पठार का 8.1 तीव्रता, 1905 में कांगड़ा का 7.8 तीव्रता, बिहार-नेपाल सीमा का 1934 में 8.3 तीव्रता और 1950 में अरुणाचल-चीन सीमा पर 8.5 तीव्रता के भूकंप दर्ज हैं। उन्हें तो हमारी पीढ़ी देख-महसूस नहीं कर सकी, लेकिन ये इतिहास के सबसे घातक और भयावह भूकंप थे। अभी एक रपट के हवाले से आकलन किया गया है कि यदि 7 तीव्रता का भूकंप आता है, तो राजधानी दिल्ली की 80 फीसदी इमारतें 'असुरक्षित' हैं। भूकंप के रूप में हिमालयी पट्टी सबसे संवेदनशील मानी जाती है। इस क्षेत्र में लगभग 2400 किलोमीटर में उच्च तीव्रता के कई भूकंप आ चुके हैं। बर्बादी भी खूब हुई है। बुनियादी कारण हिमालयी थ्रस्ट है, जिसके साथ हिमालयी वेज के नीचे भारतीय प्लेट पर जोर पड़ रहा है, नतीजतन भूकंप बार-बार और अनेक आ रहे हैं। हाल ही में दावा किया गया था कि शीघ्र ही वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भूकंप कब आ सकता है। कमोबेश भूकंप आने से कुछ पहले आगाह किया जा सकता है। वह अध्ययन किन आधारों पर किया जा रहा है, हम नहीं जानते। जब कुछ ठोस सामने आएगा, तो हम भी विश्लेषण करेंगे। लोगों को सचेत रहना चाहिए कि जब भूकंप एक बार आता है, तो बार-बार भी वह आ सकता है। बचाव जरूरी है।

राय

बंदरमुक्त कैसे होंगे

क्या बंदर अब भी जंगल की अमानत है या इससे इनसान का मुकाबला नहीं है, फिर भी मनुष्य के अस्तित्व के प्रश्न पर मानवता हावी रहती है। वन्य प्राणी सुरक्षा कानून ने बंदर को ऐसी प्रजाति तो नहीं माना कि इसकी ओर घातक निगाह से न देखा जाए, फिर भी बंदिश यह है कि जंगल के भीतर इससे अमंगल न किया जाए। इस बार सवाल उत्पाती बंदर को मारने की अनुमति का है, तो जिक्र हिमाचल की आबादी के सामने इससे जुड़े प्रकोप का भी है। यानी जनता चाहे तो वह उत्पाती बंदर की तरफ कोई खूंखार पत्थर उछाल दे, लेकिन धर्म की आंख से अभी तक यह निशाना नहीं बना जो गोली से ऐसी शरारतों का खात्मा कर दे। एक बार धूमल सरकार ने बाकायदा अभियान चलाया और कुछ शूटर काम पर लगाए गए, लेकिन तब के तथाकथित नेशनल मीडिया खास तौर पर एक न्यूज चैनल के हिमाचली एंकर ने इस कार्रवाई को बारूद बना दिया। जाहिर है वन विभाग एक ऐसा पहरा है जो हिमाचल के प्रति सख्तियों का थानेदार तो बनना चाहता है, लेकिन अपनी वजह से उत्पन्न मानवीय परेशानियों की जिम्मेदारी नहीं लेता। वन्य प्राणी भी इसी तरह की एक भूली सी जिम्मेदारी है। बंदर क्या जाने जंगल की सीमा। सुबह किसी की छत या पेड़ पर फल उजाड़ दे और फिर शाम को शरारत के साथ जंगल के अभयारण्य में खुद को संरक्षित कर ले। जाहिर है हिमाचल की सत्तर फीसदी भूमि पर खड़ा जंगल कब अपनी सरदारी घोषित कर दे, इसका न सामाजिक जीवन को आभास है और न ही विकास के रास्तों को पता। यह कैसा वन संरक्षण जो चैन से प्राकृतिक संसाधनों से प्रदेश की मुलाकात में बाधक बना रहता है। मूल विषय तो यह होना चाहिए कि वन्य प्राणी अगर जंगल से बाहर उत्पात मचा रहे हैं, तो यह जंगलात की नीति और प्रबंधन का दोष है। यहां बंदरों और जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान का आकलन भी होना चाहिए ताकि इसकी भरपाई की जा सके।

आश्चर्य यह कि अगर प्रदेश को अपनी विकास की गाड़ी जंगल के रास्ते गुजारनी पड़ती है, तो इसके बदल उतनी ही तादाद में हरियाली तथा कीमत चुकानी पड़ती है, मगर जब जंगल के जानवर बस्ती में जीना और खेत में खेती हराम करते हैं, तो वन विभाग की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, चंबा व सिरमौर के कुछ हिस्सों में जंगलों के अधीन आई जमीन सौ फीसदी इनसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन वहां के वनों ने मानव बस्तियों को घिनौने अनुभव से घेर रखा है। हमीरपुर के ही बड़सर-बिझड़ी जैसे इलाकों में वन संपदा के दंश झेलती खेती उजड़ चुकी है। किसान बंदर को जंगल की अमानत नहीं, अपनी बर्बादी का ऐसा दूत मानते हैं जिसे वन विभाग का प्रश्रय हासिल है। बंदरों की नसबंदी के जो आंकड़े दिए जाते हैं, वे प्रमाणित नहीं होते। अगर ऐसा प्रमाणित होता तो बस्ती के करीब बंदर की शुमारी कम हो जाती, परंतु सामाजिक परिदृश्य बताता है कि हर साल और साल में कई बार बंदरों की नस्ल नया व भयावह स्वरूप अख्तियार कर रही है। ऐसे में आक्रामक बंदर के खिलाफ हथियार खोलने की अनुमति भले ही प्रशंसनीय लगे, मगर इसके लिए राज्य की ओर से संकल्प जरूरी है। संकल्प वन, बागबानी, कृषि व प्रशासन के साथ मिल कर यह तय करे कि हर साल कितने खेत या बागान बंदरों से मुक्त होंगे। ये सारे विभाग किसान और बागबान के साथ-साथ आम इनसान को यह शपथपत्र दें कि कौनसा इलाका बंदर मुक्त घोषित होगा तथा इसके परिप्रेक्ष्य में कितनी सफलता अर्जित हुई, वरना चाहे कितनी भी घोषणाएं बंदरों के उत्पात के खिलाफ हो जाएं, इनसे आजिज लोगों के आंसू पोंछने का प्रमाण नहीं मिलता। सरकार को व्यापक स्तर पर बंदरों से निपटना होगा।

छोटी फिल्मों के बड़े सरोकार

राजेंद्र राजन

नस्ल, जाति, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें फिल्मकार अपनी थीम बना रहे हैं। समाज के उजले विषयों पर कम फिल्में हैं

हाल ही में शिमला में सम्पन्न अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीन की गयीं अधिकांश फिल्में विषय विविधता, कहानी कहने की अनूठी कला, मानवीय रिश्तों में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, जेंडर समस्या व खुद के लिये जीने लायक स्पेस अर्जित करने की छटपटाहट के लिये याद की जाएंगी। कला, साहित्य व फिल्मों की सृजनात्मक विधाएं भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर हर देश में लोगों को प्यार, मोहब्बत व संवेदना के स्तर पर 'वसुधैव कुटुम्बकम' की तरह जोड़ती हैं। फिल्म में अगर संवाद न भी हो तो उसकी 'विजुअल लैंग्वेज' यानी दृश्य भाषा स्वतः ही फिल्म की कहानी को बयान कर देती है। शिमला फिल्मोत्सव का यह नौवां संस्करण था। करीब एक दशक की यात्रा में शिमला के गेयटी थियेटर में हर साल उमडने वाले सिने प्रेमियों के सैलाब से स्पष्ट है कि दर्शकों के अन्तर्मन को झिंझोडने वाली फिल्में हर दौर में अपनी सार्थकता साबित कर ही लेती हैं। पुष्पराज व देवकथा के सांझे प्रयासों से इस बार दुनिया भर से 106 फिल्मों का चयन हुआ जिनमें से 38 फिल्में 20 देशों से पहुंची तो भारत के 24 राज्यों में से 63 फिल्मों के अलावा हिमाचल श्रेणी में 5 फिल्मों ने अपनी-अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह सही है कि शिमला का आकर्षण देश-विदेश के फिल्मकारों को अपनी नैसर्गिक छटा के बल पर खींचता है। सन-1889 में निर्मित गेयटी थियेटर में करीब 15 साल पहले सिनेमा स्क्रीनिंग के लिये एक प्रोफैशनल प्रेक्षागृह का निर्माण हुआ तो फिल्म रसिकों ने इसका भरपूर उपयोग किया। ऐसे समारोहों के आयोजन में प्रदेश सरकार के भाषा विभाग का सहयोग काबिले तारीफ है। इस फैस्टिवल को जिस बड़े पैमाने पर अनेक संस्थाएं 'स्पान्सर' कर रही हैं, उससे पता चलता है कि चन्द सालों में ही यह फिल्मोत्सव अनेक 'माइल स्टोन' हासिल करने में कामयाब रहा है।

इस साल फिल्मोत्सव का एक और आकर्षक व शानदार पहलू था नाहन, कण्डा जेलों में कैदियों के लिये फिल्मों का प्रदर्शन। शिमला के करीब ढली में 'विशेष बच्चों' के लिये भी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। सिनेमा जैसे सशक्त माध्यम को 'माल रोड कल्चर' से बाहर निकालकर दीगर संस्थानों में ले जाना वास्तव में सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध होने का परिचायक है। जिन देशों की फिल्मों का फिल्म फैस्टिवल में चयन हुआ उनमें अमेरिका, बेलजियम, इरान, कैनेडा, चीन, चेक रिपब्लिक, तुर्की, नेपाल, मिश्र, बांग्लादेश, इटली, पोलैण्ड, अर्जेन्टीना, स्वीडन, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, फ्रांस और दुबई शामिल हैं। लेकिन पुरस्कारों की बात करें तो फारसी ज़बान में निर्मित इरान की फिल्मों की धूम रही। 'नरेगेसी' और 'फार द सेक आफ आवा' और अफगानिस्तान की 'रोया', 'बांग्लादेश की नारी', 'चेक रिपब्लिक की' 'सेवन थाऊसेन्ड सोलस', को अन्तरराष्ट्रीय श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। गुवाहटी की फिल्म मेकर रूपम ज्योति मालांकर की फिल्म 'एकाकी' ने भी दर्शकों को ध्यान खींचा। 'नरेगेसी' में एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष को उकेरा गया है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मगर वो प्यार की तलाश में है ताकि शादी रचाकर 'खुशियां' बटोर सके। लेकिन स्वार्थी दुनिया में उसके जैसे लोगों के लिये कोई जगह नहीं है। लेकिन एक उपहार उसके जीवन को बदल देता है। 'फॉर द सेक ऑफ आवा' एक ऐसी लडक़ी 'आवा' की कहानी को बयां करती है जो दूसरे देश में एक समारोह में अपनी प्रस्तुति देने के लिये जाना चाहती है, लेकिन उसके पास न तो जन्म प्रमाण पत्र है, न ही पासपोर्ट। कारण, उसकी माता इरान से है और पिता अफगानी। 'रोया' अफगानी फिल्म है जो अपने विषय से दर्शकों को स्तब्ध कर देती है। इसे उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री को भी दिखाया गया। इस फिल्म ने दर्शकों को बांधे रखा। फिल्म में एक अफगान और उसकी पत्नी एक दल के साथ अफगानिस्तान की सीमा पार कर यूरोप में $गैर कानूनी ढंग से दाखिल होने के लिये भय, आतंक के माहौल में मीलों का सफर पैदल तय करते हैं। बियावान और मरूस्थल में। उसकी गर्भवती पत्नी प्रसव पीड़ा के कारण रोने चिल्लाने लगती है। लेकिन मानव तस्करी का सरगना उसे व उसके पति को खामोश रहने के वास्ते उन्हें बेरहमी से पीट तक देता है। औरत बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। फिल्म के अन्त में आदमी के हाथ में नवजात है और पत्नी की लाश एक पत्थर की शिला पर। तस्कर उसे छोड़ जाते हैं। वह तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए? इस फिल्म का नैरेटिव इस कदर दर्दनाक व मर्मान्तक है कि दर्शक चाहकर इस फिल्म की खौफज़दा कहानी से उबर नहीं पाते।

बांग्लादेश की फिल्म 'नारी' भी एक पुरस्कृत फिल्म है। फिल्म में एक साथ पांच स्त्री किरदारों की यातना को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। औरत की व्यथा को लैंस के माध्यम से सशक्त भावों से पकडने का प्रयास किया गया है। यह नारी की स्वतन्त्रता और अधिकारों की दुःखभरी कहानी है। इस फिल्म में एसिड अटैक, भ्रूणहत्या, गैंगरेप, बाल विवाह और बौनी औरत की कहानियां हैं। यानी औरतों पर जुल्मों-सितम के विमर्श को केन्द्र में लाती है यह फिल्म। राष्ट्रीय श्रेणी में असमिया शार्ट फिल्म 'एकाकी' को पुरस्कार मिला। फिल्म में 75 वर्षीय विभा नाम की औरत है जो अकेलेपन का दंश झेलने को अभिशप्त है। यह दुनियाभर में अकेले रह रहे बुजुर्गों की गाथा को बयान करती है। समारोह में अनेक ऐसी फिल्में भी दिखाई गयीं जो पुरस्कार प्राप्त भले ही न कर सकी हों लेकिन लीक से हटकर विषयों व उनकी शानदार ट्रीटमेन्ट के लिये यादगार बन गयी हैं। इनमें व्हाइट रोज़ज, सास, चार धाम, अनकही, उस पार, होड़, लाड़ी सूरमा, जुआरे उल्लेखनीय फिल्में हैं। ज्यादातर फिल्मों को देखकर यही लगता है कि दुनिया का हर समाज और देश अंधेरे में जी रहा है। एक ऐसा घनीभूत अंधेरा जिसने मानवता को अपने क्रूर पंजों की गिरफ्त में ले रखा है। नस्ल, जाति, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक ज्वलन्त मुद्दें हैं जिन्हें फिल्मकार अपनी थीम बना रहे हैं। समाज के उजले, सुन्दर व सकारात्मक ऊर्जा भर देने वाले विषयों पर कम ही फिल्मकारों की निगाह टिकती है। यानी मुद्दे आधारित फिल्मों का निर्माण। विविध विषयों के बल पर ये फिल्में दर्शकों के दिलों में अमिट छाप अंकित करने में सफल रही हैं। बहरहाल हिमाचल के लिए फिल्म नीति फाइलों में दफन है। सुक्खू सरकार को फिल्म नीति बनाने पर विचार करना चाहिए।

अंधी जमात के वारिस

इतना वक्त गुजर गया, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। कल तक जो अपने आपको नवांकुर कह कर उनके गमलों में रोपित हो जाना चाहते थे, आज वह अचानक बरगद बन कर उन्हें अपने साये से महरूम कर देना चाहते हैं। कल तक जो उन्हें क्रांतिकारी कह उन पर आलोक आरोपित कर उसकी विरासत का ध्वज जो जाना चाहते थे, आज उन्हें बीते जमाने की अंधेरी परछाई कह उससे यूं अलग हुए कि जैसे चिहुंक कर कहते हो, 'छाया मत छूना मन। हो जाएगा दुख दूना मन।' वे लाख उन्हें गलत कह दें, सच सच चिल्ला दें, बस्ता ढोने से कहीं बेहतर है अपना ग्रन्थ आप रचने का दावा करना। आजकल जल्दी समझ आ जाती है, किसी ज्योति स्तम्भ से आलोकित होने की बजाय, उसके समानान्तर अपना ज्योति स्तम्भ स्थापित कर देने का शुबहा पैदा कर देना। यह सच है जो आज उनके आंगन में झूठ था, वह हमारे आंगन में सच का श्रृंगार बनेगा, तभी तो हमारी मौलिकता, हमारे अलगाव की ताजपोशी होगी। ऐसा उन्होंने सबको बता दिया। इसीलिए तो आज सहज स्वीकार से अधिक सार्थक आक्रामक नकार हो गया है। हर बदलाव के आंदोलन का सामना करने का एक ही तरीका है, पहली जितनी देर हो सके, उसके सुगबुगाते हुए वजूद की अवहेलना कर दो, फिर अपनी मूर्तिभंजक भूमिका से किसी ऐसे दरकिनार कर दिये गये तर्क के ढांचे को शिरोधार्य कर वाचाल स्वर में उसका प्रतिस्थापन कर दो। बदलाव की पहली आवाज खुद ही शर्मिन्दा होकर गूंगी हो जाएगी। आपका विकल्प के रूप में उत्पन्न झूठा सच ही बदलाव की बयार बन जायेगा। पुरोधा को नकार कर ही भविष्य पुत्र पैदा होते हैं। समय हमेशा आने वाले कल को आशीर्वाद देता है, बीते कल के लिए तो आजकल कोई विदागान भी नहीं गाता।

यह वक्तव्य अपनी दाढ़ी खुजाते एक भविष्य जीवी नागरिक अपने समकक्ष दूसरे सत्य की पैरवी करते हुए समकालीन जुझारुओं के लिए कहा था, कि जिनकी समकालीनता छीन उन्हें पिटा हुआ बोसीदा सच कह उन्हें पटरी से उतार देने में ही जैसे अपना क्रांतिबोध मारक बना रहे थे। लीजिये एक क्रांति संभाषण से बड़ा बन कर दूसरा संभाषण उससे टकराया। टकरा कर ये सब संभाषण तो अपनी सफलता की मंजिलें तय करते चल गए, नीचे धरती तल पर रह गये वे करोड़ों लोग, जिन्हें अपने कंधों पर बैठाकर इन भाषणबाजों ने उड़ान भरनी थी। उड़ान तो उनकी जारी है, परन्तु इस उडनखटोले पर सवार हैं उनके नाती-पोते, जो कभी उनके अपने आदमी थे, वही बन गये वंशज, जिनके पत्तों पर तकिया वही अब उन्हें हवा देता कह कर इधर-उधर बिखरा दिये गए। प्रगति के रास्ते पर सत्ता की दलाली के इतने टीले खड़े हो गये कि परिवर्तन की पुकार नासमझी लगने लगी है। और हर क्रांति की हुंकार बड़ी हवेलियों के द्वार से अपनी प्राण वायु के लिए कतार लगाती दिखने लगी है। निवेश के आकाशचारियों ने तरक्की के नये आसमान छू लिये, जो धनपति थे, और परिवर्तन के नाम पर मरते निवेश को जिंदगी दे देने का दावा कर रहे थे, वे तो दुगनी तरक्की कर गये और उनकी कतार से बहिष्कृत लोगों की रोजी-रोटी भी गई। उखड़े हुए लोगों के भाग्य में तो उखडना ही लिखा होता है। उनका बेकार युवा बल गांवों से उखड़ता है तो शहरों की ओर धंधा पाने का रुख करता है। कोरोना की मृत्युवाहिनी की ध्वनि ने उन्हें शहरों की गंदी बस्तियों से उखाड़ कर वापस गांवों की ओर फेंका कि जाओ एक नये कृषक भारत का निर्माण करो, लेकिन वहां तो वहीं ऊसर वीरानी थी और धनाढ्य साहूकार, दलालों और जमीदारों के पास बंधक पड़े बंटाईदार थे। उनके लिए जगह न वहां थी, न शहर में। अब तो विदेशों में दोयम दर्जे की नागरिकता का आसरा भी न रहा। इसलिए बेकारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की स्पूतनिक गति से भटकते आंकड़े उन्हें नारों के एक अन्धे कुएं से दूसरे कुएं में डाल देते हैं। अन्धे कुओं की यह कैसी विरासत है, जो कानून बदलाव की क्रांति को एक शुबहे में बदल देती है। असल किसान क्रांति की खोज में जो देश की राजधानी पर लाखों व्यग्र लोगों का धरना लगा है, उसे भी एक शुबहे में बदलने की खोज करने वाले कम नहीं रहे।

सुरेश सेठ

दूसरे दिन की बैठक खत्म, महंगाई पर आरबीआई का ज्यादा ध्यान, रेपो रेट रह सकता है स्थिर

RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। 4 से 6 अक्टूबर तक चलने वाली बैठक के फैसलों की घोषणा कल सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। द्विमासिक बैठक के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति की चिंताओं और अन्य वैश्विक कारकों के कारण रेपो दर को फिर से 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रख सकता है।

नई दिल्ली: कल से शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति का आज दूसरा दिन था। 4 से 6 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में लिए जाने फैसलों को कल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 10 बजे सुबह सुनाएंगे।

रेपो रेट इस बार भी रह सकता है स्थिर

हर दो महीनों में एक बार होने वाली इस बैठक के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने कहा कि मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और अन्य वैश्विक कारकों के बीच आरबीआई इस बार भी रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रख सकता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई को क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी जोशी ने बताया कि

मुझे लगता है कि अगस्त में पिछली एमपीसी बैठक और इस बार के बीच, मुद्रास्फीति बढ़ी है, विकास मजबूत बना हुआ है, जबकि वैश्विक कारक इस अर्थ में थोड़े प्रतिकूल हो गए हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अभी भी अपने रुख में आक्रामक है, जिससे सख्त पैदावार का रुख आया है। ऐसे में केंद्रीय बैंक से आगामी नीति में नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद है

महंगाई पर आरबीआई का ज्यादा ध्यान

डी जोशी के मुताबिक आरबीआई मुद्रास्फीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा क्योंकि विकास अभी मजबूत है, साथ ही तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर भी सावधानी से नजर रखने की जरूरत है।

सरकार ने आरबीआई को क्या दिया आदेश?

केंद्र सरकार ने आरबीआई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर स्थिर रखने को कहा है जिसमें 2 प्रतिशत का दोनों तरफ मार्जिन हो।

जुलाई में थी रिकॉर्ड महंगाई

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।

आखिरी बार आरबीआई ने कब बढ़ाया था रेपो रेट

आखिरी बार आरबीआई ने रेपो रेट में फरवरी 2023 में बदलाव किया था। दरअसल रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर आरबीआई ने मई 2022 में रेपो रेट को को किश्तों में बढ़ाना शुरू किया था और इस साल फरवरी में रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर ले आया।

भेल ने भरा सरकार का खजाना, वित्त वर्ष 23 के लिए दिया 88 करोड़ रुपये का डिविडेंड

सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंपनी BHEL ने आज अपने मुनाफे का हिस्सा सरकार को सौंप दिया। बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में केंद्र सरकार को 88 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। BHEL में भारत सरकार की 63.17% हिस्सेदारी है। लाभांश का चेक आज भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नलिन शिंगल ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को सौंपा।

नई दिल्ली: सरकारी इंजीनियरिंग फर्म बीएचईएल (BHEL) ने आज सरकार को अपना प्रॉफिट का हिस्सा दिया। बीएचईएल ने केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फाइनल डिविडेंड के रूप में 88 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

सरकार के पास कितनी है हिस्सेदारी?

बीएचईएल में भारत सरकार के पास कंपनी की 63.17 प्रतिशत हिस्सेदारी है। डिविडेंड का चेक आज बीएचईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नलिन सिंघल (Nalin Shinghal) ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को दिया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के शेयरधारकों को भुगतान किया गया कुल लाभांश 139 करोड़ रुपये से अधिक है।

कैसा रहा आज BHEL का शेयर?

गुरुवार 5 सितंबर को बीएचईएल का शेयर बाजार में सपाट स्तर पर बंद हुआ। आज कंपनी का शेयर 127 रुपये पर बंद हुआ।

क्या है बीएचईएल?

बीएचईएल की आधिकारीक वेबसाइट के मुताबिक, बीएचईएल ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम है।

इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह विश्व स्तर पर एक अग्रणी बिजली उपकरण निर्माता हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सबसे शुरुआती और अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक है। बीएचईएल के पास पावर-थर्मल, हाइड्रो, गैस, परमाणु और सौर पीवी के क्षेत्रों में उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं, संचरण, परिवहन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, तेल एवं गैस और बीईएसएस और ईवी चार्जर जैसे नए क्षेत्र जैसे पोर्टफोलियो है।

कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 405 अंक बढ़ा

कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ है। कच्चेतेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। बैंकिंग और आईटी शेयर बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स चार्ट में आज लार्सन एंड टुब्रो टॉप- गेनर रहे। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 83.27 पर बंद हुआ।

नई दिल्ली। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज सुधार के बीच पूंजीगत वस्तुओं, बैंकिंग और आईटी शेयरों में तेजी के बाद गुरुवार के सत्र में बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी से उछाल आया।

आज बीएसई सेंसेक्स 405.53 अंक या 0.62 प्रतिशत बढ़कर 65,631.57 पर बंद हुआ, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 109.65 अंक या 0.56 प्रतिशत बढ़कर 19,545.75 पर पहुंच गया।

टॉप गेनर्स और लूजर्स स्टॉक

सेंसेक्स पैक में लार्सन एंड टुब्रो 2.35 फीसदी की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहे। इसके बाद टाइटन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स रहे। वहीं, पावर ग्रिड, नेस्ले, एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बजाज फाइनेंस के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।

वैश्विक बाजार का हाल

एशियाई बाजारों में, टोक्यो और हांगकांग हरे निशान में बंद हुए, जबकि सियोल निचले स्तर पर बंद हुआ। शंघाई में छुट्टी के कारण कारोबार बंद था। यूरोपीय बाजार मिश्रित रुख पर कारोबार कर रहे थे। बुधवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.89 प्रतिशत गिरकर 85.05 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 4,424.02 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची।

कल लाल निशान पर बंद हुआ बाजार

बीते दिन बुधवार को बीएसई बेंचमार्क 286.06 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65,226.04 पर बंद हुआ। निफ्टी 92.65 अंक या 0.47 प्रतिशत फिसलकर 19,436.10 पर बंद हुआ।

वेज और नॉन वेज थाली की कीमतों में आई कमी, पिछले महीने 62 प्रतिशत सस्ता हुआ था टमाटर

सितंबर में टमाटर की कीमत में आई कमी के कारण वेज और नॉन वेज थाली की कीमतों में कमी आई है। सितंबर में टमाटर के दाम गिरकर 39 रुपये प्रति किलो पर आ गए जो 62 प्रतिशत की गिरावट है। अगस्त में टमाटर की कीमत 102 रुपये थी। हालांकि अभी भी प्याज की कीमत बढ़ी हुई रह सकती है। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

नई दिल्ली: देश में टमाटर की कीमतों में आई कमी का असर अब वेज और नॉन वेज थाली पर भी दिख रहा है। पिछले महीने यानी सितंबर में टमाटर की गिरती कीमतों के कारण देश में वेज और नॉन वेज थाली में गिरावट देखने को मिली है।

कितना सस्ती हुई थाली?

क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के भोजन की थाली की लागत के मासिक संकेतक - रोटी चावल दर (आरआरआर) के अनुसार, सितंबर में शाकाहारी थाली की कीमत 17 प्रतिशत और गैर-शाकाहारी थाली की कीमत 9 प्रतिशत गिरी है।

62 प्रतिशत सस्ता हुआ टमाटर

आपको बता दें कि सितंबर में टमाटर गिरकर 39 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। टमाटर की कीमत में महीने-दर-महीने 62 प्रतिशत की कमी आई है। अगस्त में टमाटर की कीमत 102 रुपये प्रति किलोग्राम थी। वेज और नॉन वेज थाली की कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण टमाटर है।

सालाना आधार पर 1 प्रतिशत सस्ती हुई वेज थाली

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, साल-दर-साल आधार पर, सितंबर में शाकाहारी थाली की कीमत में 1 प्रतिशत की मामूली कमी आई है जबकि गेहूं और पाम तेल की ऊंची कीमतों के कारण नॉन-वेज थाली की कीमत में 0.65 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है।

12 प्रतिशत बढ़ी प्याज की कीमत

रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में प्याज की कीमतें महीने-दर-महीने 12 प्रतिशत बढ़ीं है और फिलहाल यह कीमत यही बनी रहेगी क्योंकि खरीफ 2023 का उत्पादन कम होने की उम्मीद है।

ईंधन के दाम का शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की कुल लागत में क्रमशः 14 प्रतिशत और आठ प्रतिशत योगदान रहता है। इसमें सितंबर में क्रमिक रूप से 18 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपये से घटकर 903 रुपये हो गई।

ईंधन के दाम का शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की कुल लागत में क्रमशः 14 प्रतिशत और आठ प्रतिशत योगदान रहता है। इसमें सितंबर में क्रमिक रूप से 18 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपये से घटकर 903 रुपये हो गई।

मिर्च की कीमतों में आई कमी

रिपोर्ट के मुताबिक मिर्च की कीमतों में भी कुछ राहत मिली है क्योंकि पिछले महीने की तुलना में कीमतों में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है। सितंबर में मिर्च की औसत कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अगस्त में 44 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

फिर से गिरा सोने का भाव, चांदी की बढ़ी चमक, जानिए आपके शहर में क्या है गोल्ड की कीमत

सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रही है हालांकि आज चांदी की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आज किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत कितनी है। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

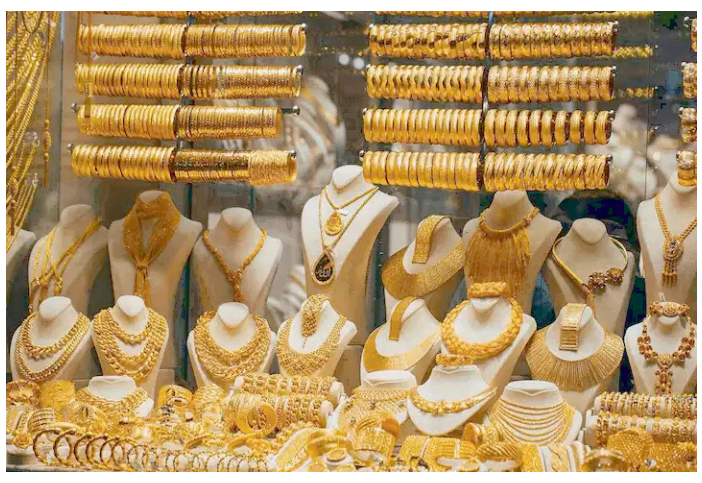

नई दिल्ली: सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है वहीं चांदी की कीमतों में आज तेजी आई है।

अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आज आप इसे सस्ती कीमतों पर खरीद पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे की आपके शहर में क्या है सोने का 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का भाव।

क्या है सोने का भाव?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत 150 रुपये घटकर 57,350 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई।

वहीं पिछले कारोबार में सोना 57,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय कारोबार में सोना गिरावट के साथ 1,820 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

क्या है चांदी का भाव?

आज चांदी की कीमत 300 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। चांदी 300 रुपए चढ़कर 71,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी तेजी के साथ 21.15 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी।

वायदा कारोबार में सोना

आज वायदा कारोबार में सोने की कीमत 10 रुपये गिरकर 56,711 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 10 रुपये या 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,711 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 16,193 लॉट का कारोबार हुआ।

वायदा कारोबार में चांदी

आज वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 329 रुपये बढ़कर 67,214 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 329 रुपये या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 29,667 लॉट में 67,214 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

आपके शहर में क्या है सोने की कीमत?

गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक सोने की कीमत इस प्रकार है:

दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,310 रुपये है।

नोएडा में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,310 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,160 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,760 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,160 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,160 रुपये है।

केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,160 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,210 रुपये है।

सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,210 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,310 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,310 रुपये है।

अब तक सरकार ने 12.21 लाख टन खरीफ धान खरीदा, ई-नीलामी के जरिये बेचा गेहूं-चावल

सरकार ने खरीफ धान की खरीदारी शुरू कर दी है। इस वर्ष थोड़े अधिक क्षेत्रफल 411.96 लाख हेक्टेयर में बोए गए खरीफ धान की कटाई पिछले सप्ताह शुरू हुई। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम ने बुधवार को आयोजित 15वीं साप्ताहिक ई-नीलामी में आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं को 1.89 लाख टन गेहूं और केवल 5000 टन चावल बेचा।

नई दिल्ली। खाद्य मंत्रालय के अनुसार सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी है। अब तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लगभग 12.21 लाख टन अनाज खरीदा जा चुका है। मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में 99,675 किसानों से एमएसपी पर 2,689.77 करोड़ रुपये का धान खरीदा गया है।

इस वर्ष थोड़े अधिक क्षेत्रफल 411.96 लाख हेक्टेयर में बोए गए खरीफ धान की कटाई पिछले सप्ताह शुरू हुई।

भारतीय खाद्यनिगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों ने बफर स्टॉक बनाने के साथ-साथ किसानों के हितों की रक्षा के लिए एमएसपी पर खरीद शुरू की है। मंत्रालय ने चालू सीजन में 521.27 लाख टन की खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि एक साल पहले के सीजन में वास्तविक खरीद 496 लाख टन थी।

ई-नीलामी में बेचा गेहूं और चावल

राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने बुधवार को आयोजित 15वीं साप्ताहिक ई-नीलामी में आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं को 1.89 लाख टन गेहूं और केवल 5,000 टन चावल बेचा। घरेलू उपलब्धता में सुधार और खुदरा कीमतों को कम करने के लिए थोक उपयोगकर्ताओं को खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं और चावल बेचे जा रहे हैं। खाद्य मंत्रालय के अनुसार 4 अक्टूबर को आयोजित साप्ताहिक ई-नीलामी में 2.01 लाख टन की पेशकश के मुकाबले लगभग 1.89 लाख टन गेहूं बेचा गया। हालांकि, एफसीआई को ओएमएसएस के तहत चावल की साप्ताहिक ई-नीलामी के लिए फीकी प्रतिक्रिया मिलती रही और व्यापारियों ने 4.87 लाख टन की पेशकश के मुकाबले केवल 5,000 टन अनाज खरीदा। ई-नीलामी के दौरान 2,255 बोलीदाताओं को गेहूं और चावल बेचे गए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, गेहूं और चावल दोनों के लिए लगभग 2,447 सूचीबद्ध खरीदारों ने भाग लिया।

पूरे भारत में चावल के लिए भारित औसत बिक्री मूल्य 2,932.91 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आरक्षित मूल्य 2,932.83 रुपये प्रति क्विंटल था। मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ई-नीलामी में छोटी मात्रा की पेशकश की जा रही है।

वर्ल्ड कप 2023 का हुआ आगाज, फेस्टिव सीजन के दौरान बिजनेस पर दिखेगा कुछ ऐसा असर

ICC World Cup 2023 देश में जहां एक ओर Festive Season की शुरुआत होने वाली है तो वहीं आज से ICC World Cup 2023 की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। व्यापारियों का मानना है कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में उनका कारोबार में तेजी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि ICC World Cup 2023 का बिजनेस पर कैसे असर पड़ेगा?

नई दिल्ली। करीब 12 साल के बाद भारत में दोबारा से आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (ICC World Cup 2023) का आयोजन हो रहा है। इस बार भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। 45 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में 48 मैच होंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है।

पूरा देश इस टूर्नामेंट को जीतने की उम्मीद कर रहा है वहीं, कई निवेशक और ब्रांड का मानना है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही उनके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में भारत में आयोजित विश्व कप (World Cup) में हर मैच में औसतन 25,000 दर्शक मौजूद थे। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में क्रिकेट को कितना ज्यादा पसंद किया जाता है।

कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट का असर बिजनेस के कई सेक्टर पर पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में मैच के दिनों में, मूवी थिएटरों, थीम पार्कों और ऑफलाइन इवेंट में दर्शकों की संख्या में कमी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट, मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग के दर्शकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

भारत में क्रिकेट का प्यार

भारतीयों के बीच क्रिकेट कितना लोकप्रिय है। इसकी बानगी सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के फॉलोअर्स की संख्या से लगाया जा सकता है। इंस्टाग्राम (Instagram) पर टॉप-10 क्रिकेट प्लेयर में से 4 भारतीय क्रिकेटर हैं। इसमें सबसे टॉप पर विराट कोहली (Virat Kohli) हैं।

आपको बता दें कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा खर्च क्रिकेट पर होता है। इसे आसान तरीके से समझिए की हर साल 85 फीसदी खर्च क्रिकेट पर और बाकी 15 फीसदी अन्य खेलों पर किया जाता है। पिछले दशक से आईपीएल (IPL) का क्रेज बढ़ गया है। वहीं भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली कमेटी बीसीसीआई (BCCI) ने पिछले 16 साल में 10 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। आइए, अब जानते हैं कि विश्व कप का भारत के किस बिजनेस सेक्टर पर कितना असर पड़ता है?

किन सेक्टर पर पड़ेगा पॉजिटिव असर

विश्व कप की वजह से अगले दो महीनों कई बिजनेस से प्रॉफिट की उम्मीद है। देश में वैसे ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से होटल और एयरलाइन को सबसे ज्यादा का लाभ मिलेगा। इसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि देश जब इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है तो विदेशी टीमों के खिलाड़ियों के साथ कई और विदेशी भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आएंगे। ऐसे में एयरलाइन को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा।

गगनयान मिशनः क्रू एस्केप सिस्टम के इनफ्लाइट एबॉर्ट का परीक्षण, अक्तूबर के अंत में इसरो कर सकता है परीक्षण

परिवहन विशेष न्यूज

देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान (गगनयान) के तहत इसरो क्रू एस्केप सिस्टम का इनफ्लाइट एबॉर्ट परीक्षण करने तैयारी कर रहा है। वीएसएससी के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर ने कहा, सभी वाहन प्रणालियां प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा पहुंच चुकी हैं।

देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान (गगनयान) के तहत इसरो क्रू एस्केप सिस्टम का इनफ्लाइट एबॉर्ट परीक्षण करने तैयारी कर रहा है। इसरो के मुताबिक इस माह के अंत में यह परीक्षण होने की संभावना है। इस उद्देश्य में इस्तेमाल होने वाले परीक्षण वाहन का उपयोग करते हुए यह परीक्षण किया जाएगा।

अक्तूबर के अंत तक परीक्षण की उम्मीद

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर ने कहा, सभी वाहन प्रणालियां (प्रक्षेपण के लिए) श्रीहरिकोटा पहुंच चुकी हैं। अंतिम असेंबली चल रही है। हम अक्तूबर के अंत तक प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, इस क्रू एस्केप सिस्टम के साथ उच्च गतिशील दबाव और ट्रांसोनिक स्थितियों जैसी कई स्थितियों में प्रदर्शन किया जाएगा।

कई चरणों के जरिए देंगे सफलता को अंजाम

इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस) सबसे खास है। इस महीने परीक्षण वाहन टीवी-डी1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के चार मिशनों में से पहला होगा। इसके बाद दूसरा परीक्षण वाहन टीवी-डी2 मिशन और गगनयान (एलवीएम3-जी1) का पहला मानव रहित मिशन होगा।

परीक्षण वाहन मिशन (टीवी-डी3 और डी4) की दूसरी श्रृंखला और रोबोटिक पेलोड के साथ एलवीएम3-जी2 मिशन की अगली योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चालक दल मिशन की योजना सफल परीक्षण वाहन के नतीजे और उन मिशनों के आधार पर बनाई गई है जिनमें कोई चालक दल नहीं है।

क्या है परीक्षण वाहन?

परीक्षण वाहन एक एकल चरण रॉकेट है, जो तरल प्रणोदन पर आधारित है। जिसे कई महत्वपूर्ण मैक संख्याओं पर सीईएस प्रदर्शन को मान्य करने के लिए विकसित किया गया है। लेकिन नायर ने कहा कि इसका उपयोग अंतरिक्ष पर्यटन सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। साथ ही नायर ने कहा, अगर कोई उद्योग इसमें रुचि रखता है तो इस वाहन का उपयोग अंतरिक्ष पर्यटन के लिए किया जा सकता है। वहीं वाहन क्रू मॉड्यूल को 100 किमी तक ले जा सकता है और फिर वापस आ सकता है।

हाईफ्लायर प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाडा। संगम विश्वविधालय के प्रबंध विभाग में हाईफ्लायर प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को एक नई पहल बताया और विद्यार्थियों को उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन में प्रबंध विभाग अधिष्ठाता प्रोफेसर विभोर पालीवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रबंध के विद्यार्थियों में कौशल ज्ञान अति आवश्यक है। अनटेक के उपाध्यक्ष अनंत नेपोलिया ने कार्यक्रम की रुप रेखा के बारे मे अवगत कराया और कहा कि इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को अन्तरराष्ट्रीय प्लैटफॉर्म के माध्यम से संक्षिप्त प्रमाणपत्र और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।कार्यक्रम की मुख्य वक्ता कॉर्पोरेट प्रशिक्षक रश्मि जूही ने भावात्मक बुद्धि के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर उप कुलपति प्रोफेसर मानस रंजन और कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने विभाग को इस नई पहल के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक डॉ मुकेश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रबंध विभाग के सभी फैकल्टी सदस्य उपस्थित थे।

राज्य पुलिस का अगला प्रमुख कौन होगा?

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबानेश्वर : कोंन होंगे राज्य पुलिस के अगले मुखिया? ओडिशा के अगले पुलिस महानिदेशक का कार्यभार किसे मिलेगा? राज्य पुलिस की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? क्योंकि 31 दिसंबर को डीजी पुलिस सुनील फाउलाल रिटायर हो जाएंगे. ऐसे में अगला डीजीपी कौन होगा इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है.1989 बैच की महिला आईपीएस बी.राधिका अगले पुलिस डीजी की रेस में सबसे आगे हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी और जेल डीजी मनोज छाबड़ा, गृह विभाग के ओएसडी अरुण कुमार रॉय. इसके अलावा बीएसएफ-पूर्वी कमान के स्पेशल डीजी वाई.बी खुरानिया का नाम भी चर्चा में है. हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि महिला स्पीकर के बाद किसी महिला अधिकारी को डीजीपी का प्रभार मिल सकता है. क्यू की 2024 चुनावी वर्ष है, इसलिए कानून-व्यवस्था और चुनाव प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है।

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 का महासंग्राम शुरू, पहला मैच इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच अहमदाबाद में हुआ

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 का महासंग्राम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है जहाँ मौजूदा विश्व-चैम्पियन इंग्लैंड का मुकाबला पिछले वर्ल्डकप में उपविजेता रही न्यूज़ीलैंड से होगा।

नई दिल्ली। 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवम्बर तक चलने वाले क्रिकेट महाकुंभ में कुल 48 मैच खेले जाएंगे जानकारों के मुताबिक इस बार भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खिताब की प्रबल दावेदार रहेंगी भारत अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा भारत को घरेलू मैदानों पर और घरेलू दर्शको के सामने खेलने का फायदा मिलेगा अभी हाल ही में भारत ने एशिया-कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से जीती जिससे भारतीय टीम का मनोबल काफी बड़ा हुआ है। इसी तरह इंग्लैंड भी वर्ल्डकप जीतने वाली प्रबल दावेदार टीमो में शुमार है इंग्लैंड में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है जो किसी भी मैच का पांसा पलट सकते है इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के लिए बाकी टीमो को एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा। खिताब की प्रबल दावेदारों की लिस्ट में तीसरा नाम ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्डकप में जीत का रिकार्ड 67% है और वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया टीम काफी खतरनाक मानी जाती है और अच्छी-अच्छी टीमो को आसानी से धूल चटा देती है भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ के अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ ज़बरदस्त क्रिकेट खेला ऑस्ट्रेलिया ने मैच के हर विभाग में भारत को मात दे दी थी।

केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 में हुआ संशोधन; सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम-1995 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इसमें गैर-आपराधिक प्रावधानों को लागू करने के लिए परिचालन प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की गई है।

सूचना प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 में बड़े संशोधन किए हैं। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। इन संसोधनों के बाद अब केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम-1995 को आपराधिक धाराओं से मुक्त किया गया है। इससे पहले, हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1994 में बड़ा संशोधन किया था। अधिसूचना में बताया गया है कि संशोधन के माध्यम से कठोर दंड का सहारा लिए बिना छोटे और अनपेक्षित उल्लंघनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। इन संशोधनों से अधिनियम के अनुपालन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सलाह, आलोचना और चेतावनी शामिल होने से उल्लंघनकर्ता को दंडित होने के बजाय हितधारक अनुपालन के लिए प्रेरित होंगे।

बता दें कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम 1995 की धारा 16 किसी भी प्रावधान के तहत उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित है। इस धारा में कारावास का प्रावधान था, जिसे पहली बार के मामले में 2 साल तक और प्रत्येक बाद के अपराध के लिए 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 को और अधिक व्यवसाय अनुकूल बनाने और क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के लक्ष्य से धारा 16 के तहत निर्दिष्ट दंडों की फिर से जांच की गई और जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन के माध्यम से इसे अपराध मुक्त कर दिया गया।

हाल ही में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1994 में हुआ था संशोधन

सूचना प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने हाल ही में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1994 में बड़ा संशोधन किया था। संशोधन के बाद अब 10 साल की अवधि के लिए मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (MSO) के लिए पंजीकरण शुरू होगा। इस पंजीकरण में ब्रॉडबैंड कंपनियां भी शामिल हो सकेंगी। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एमएसओ उन कंपनियों को कहा जाता है जो टीवी के केबल सिस्टम को ऑपरेट कर रही हैं। देश में करीब 115 एमएसओ ऑपरेटर (केबल टीवी ऑपरेटर) हैं। बता दें कि इससे पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत ब्रॉडबैंड या टेलीकॉम कंपनियों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने का प्रावधान नहीं था।

अमृतसर नगर निगम के नए असिस्टेंट कमिश्नर बनने पर विशाल वधावन जी को नगर निगम के कर्मचारियों ने फूलों के गुलदस्ते के साथ किया सम्मानित

साहिल बेरी

अमृतसर। नगर निगम के सेक्रेटरी विशाल वधावन तरक्की पा कर सहायक कमिश्नर बन गए हैं। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा तीन निगम सेक्रेटरी को पदोन्नति देकर सहायक कमिश्नर नियुक्त किया है, जिनमें राजीव कुमार, राहुल शर्मा और विशाल वधावन शामिल है। लोकल बॉडी विभाग के सेक्रेटरी अजय शर्मा द्वारा जारी आदेशों पर तीनों अधिकारियों को तरक्की मिली है। पदोन्नति के आदेश आने पर विशाल वधावन को बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा।सहायक कमिश्नर की पदोन्नति के आदेश आते ही नगर निगम कमिश्नर राहुल, जॉइंट कमिश्नर हरदीप सिंह तथा नगर निगम के अन्य अधिकारियों द्वारा विशाल वधावन को बधाइयां दी गई। बता दे की विशाल वधावन साल 1999 में नगर निगम में बेतौर इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे ।इसके उपरांत वह पदोन्नति पाकर सुपरिंटेंडेंट और सेक्टरी नियुक्त हुए।इस मौके विशाल वधावन को शहरवासियों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा भी उन्हें बधाई दी जा रही है। नगर निगम के लैंड विभाग द्वारा विशाल वधावन को बधाई दी।

विभाग के सुपरिटेंडेंट धर्मेंद्र जीत सिंह, इंस्पेक्टर राजकुमार, जूनियर सहायक अरुण सहजपाल, विज्ञापन विभाग के सुपरिटेंडेंट पुष्पेंद्र सिंह ,जर्नल सुपरिटेंडेंट सतपाल,एमटीपी नरिंदर शर्मा ,सीवरमैन कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष दीपक गिल और सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान श्री विनोद बिट्टा जी और भी कर्मचारी हाजिर थे।

सरकार ने लागू किया कच्चे जूट के लिए न्यूनतम मूल्य; जानें कितने रुपये में किसान बेच सकेंगे फसल

सरकार ने ये कदम तब उठाया जब ये खबरें आई थी कि सबसे अधिक कारोबार वाली किस्म टीडी5 की औसत कच्चे जूट की कीमतें बुधवार को 4,100 रुपये तक गिर गई थीं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जूट के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। इस संबंध में जूट आयुक्त ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जूट आयुक्त मोलॉय चंद्र चक्रवर्ती ने अधिसूचना में कहा कि कृषि स्तर पर जूट की न्यूनतम कीमत 5,050 रुपये प्रति क्विंटल और कोलकाता में डिलीवरी के लिए 5,500 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि जूट को 'गोल्डन फाइबर' के रूप में भी जाना जाता है। सरकार के इस कदम की सराहना की जा रही है। बता दें कि सरकार ने ये कदम तब उठाया जब ये खबरें आई थी कि सबसे अधिक कारोबार वाली किस्म टीडी5 की औसत कच्चे जूट की कीमतें बुधवार को 4,100 रुपये तक गिर गई थीं। जूट आयुक्त मोलॉय चंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि सभी प्रकार के जूट की न्यूनतम कीमत 31 अक्टूबर तक या कच्चे जूट के किसी भी व्यापार के लिए अगले आदेश तक लागू रहेंगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस आदेश में बताई गई दरों के अलावा अन्य दरों पर कोई भी खरीदारी या लेनदेन नहीं किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में जूट किसानों ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अपनी उपज के लिए बेहतर कीमतों और एमएसपी में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

क्या 2023 होगा सबसे गर्म साल? सबसे ज्यादा तापमान बीते सितंबर में रिकॉर्ड किया गया

जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के बढ़ते तापमान से हर कोई परेशान है। इसके चलते मौसम में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। वहीं, प्राकृतिक आपदाओं में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच, यूरोपीय संघ की 'कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस' (C3S) ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। इनमें कहा गया है कि इस साल का सितंबर अब तक का सबसे गर्म सितंबर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि साल के पहले नौ महीनों में पूरी दुनिया का तापमान औसत से 0.52 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2023 अब तक का सबसे गर्म साल बनने जा रहा है।

बीते माह में औसत तापमान 16.38 डिग्री सेल्सियस

यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज द्वारा पेश किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि सितंबर 2023 अब तक का सबसे गर्म सितंबर दर्ज किया गया है। बीते माह में औसत तापमान 16.38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह 1991-2020 के महीने के औसत से 0.93 डिग्री अधिक था। इसमें यह भी बताया गया है कि अभी तक साल 2020 के सितंबर को सबसे गर्म सितंबर के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन, 2023 के सितंबर का तापमान इससे भी 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।

2023 सबसे गर्म साल बनने जा रहा

कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज ने यह भी दावा किया है कि बीते कुछ महीनों के तापमान को देखें को साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल बन सकता है। दावा किया है कि साल 2016 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, लेकिन इस साल के शुरुआत के नौ महीनों का तापमान 2016 के शुरुआत के नौ महीने के तापमान से भी 0.05 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है।

कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज की डिप्टी डायरेक्टर समांथा बर्जेस ने इस स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह वह समय है जबकि महत्वाकांक्षी जलवायु योजना जल्दी से जल्दी बनाई जानी चाहिए।

वहीं, अमेरिका के एक संगठन बर्कले अर्थ के शोधकर्ताओं ने कहा कि गर्मी की लंबी अवधि एक साथ काम करने वाले कई मानव निर्मित और प्राकृतिक कारकों से मिलकर बनी है। उन्होंने कहा कि मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान को प्रति दशक लगभग 0.19 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रही है। यह वायुमंडल में अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड के संचय का प्रत्यक्ष परिणाम है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023